

राम मंदिर चढ़ावा केस में एसआईटी फिर पहुंची अयोध्या, बैंक लेनदेन की हो रही जांच

छ.ग.फ्रंटलाइन अयोध्या। राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जांच अब तेज हो गई है। विशेष जांच दल एक बार फिर अयोध्या पहुंचा है और भारतीय स्टेट बैंक के रिकॉर्ड खंगाल रहा है, जहां चढ़ावे की रकम जमा होती रही है।

एसबीआई पहुंची जांच टीम

एसआईटी और पुलिस टीम ने एसबीआई शाखा पहुंचकर बैंक अधिकारियों से जानकारी ली।



टीम दान पेटियों से लेकर बैंक में जमा होने तक की पूरी प्रक्रिया की पड़ताल कर रही है - रकम की गिनती, रिकॉर्डिंग,

कर्मचारियों से पूछताछ

मंदिर व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों, बैंक स्टाफ और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के बैंक खातों और वित्तीय गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। एसआईटी का मानना है कि बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल दस्तावेजों से ही मामले की असली तस्वीर सामने आएगी। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि गड़बड़ी कहां हुई और कौन जिम्मेदार है।

जमा, निकासी और भुगतान के दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। जांच एजेंसियां बैंक स्टेटमेंट, भुगतान रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और कर्मचारियों

नशे में बुलेट चला रहे युवक पर कोर्ट ने

लगाया 10 हजार जुर्माना

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत इंक एंड ड्राइव के एक मामले में कार्रवाई की गई है। यातायात शाखा की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 15 ईबी 2674 का चालक रितेश शाह पिता चंद्रसेन शाह 23 वर्ष, निवासी नवानगर, थाना दरिमा मौके पर नशे में धुत मिला।

ब्रेथ एनालाइजर से जांच करने पर शराब पीकर वाहन चलाने की पुष्टि हुई। इस पर यातायात पुलिस ने चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए वाहन चालक को 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस ने बताया कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय केवर्त सहित यातायात स्टाफ सक्रिय रहा।

वित्तीय अनियमितता प्रमाणित, ग्राम पंचायत लब्जी के सचिव पदच्युत

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर। जनपद पंचायत अम्बिकापुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत लब्जी में पदस्थ सचिव अमन सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत लब्जी में वित्तीय अनियमितता करने एवं शिकायत जांच समिति के समक्ष निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने के फलस्वरूप आदेश जारी कर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आरोप पत्र के अनुसार एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने इन्हें कहा गया है। आरोप पत्र का प्रत्युत्तर समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर कार्यालयीन आदेश के तहत विभागीय जांच संस्थित करते हुए उप संचालक पंचायत को जांचकर्ता अधिकारी एवं जिला अंकेक्षक पंचायत को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि, छपरड़ा नाला के पास पुलिसिया निर्माण, सी.सी. रोड निर्माण रामलाल घर से कंवलसाय घर तक, मिडिल स्कूल शौचालय निर्माण, खेल मैदान के विकास हेतु, नाली निर्माण, आंगनवाड़ी भवन में शौचालय निर्माण, बाजार में शेड निर्माण हेतु ग्राम राशि से कार्य नहीं कराने के मामले में उक्त निर्देशानुसार विभागीय जांचकर्ता अधिकारी उप संचालक पंचायत के द्वारा प्रकरण की तथ्यात्मक जांच कर, निष्कर्ष सह जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

है। जांच प्रतिवेदन में जांच अधिकारी द्वारा उल्लेखित किया गया कि, सचिव अमन सिंह द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष अपने बचाव हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत लब्जी के निर्माण कार्यों को पूर्ण न करार रुपये 16 लाख 58 हजार 800 का वित्तीय अनियमितता किया जाना प्रमाणित पाया गया। ऐसे में अमन सिंह का अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह एवं गैर-जिम्मेदार होना सामने आया था। परीक्षण के बाद विभागीय जांचकर्ता अधिकारी के निष्कर्ष एवं सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन अनुसार पंचायत सचिव अमन सिंह के ऊपर आरोपित आरोप प्रमाणित पाया गया, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम-3 एवं छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के विपरीत होने कारण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत दण्डनीय है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने ग्राम पंचायत लब्जी के तत्कालीन सचिव के विरुद्ध आरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील), नियम 1999 के नियम-5 (ख) (सात) के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने के दण्ड से दण्डित करते हुए विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया है।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हालत देखकर कलेक्टर ने कहा-एक महीने में सब ठीक करो

सीपेज रोकने 50 लाख की स्वीकृति, नगर निगम को शीघ्र कार्य प्रांभ करने कहा

नेत्र प्रत्यारोपण की तैयारी प्रारंभ करने व पावर ऑडिट कार्य हेतु बजट उपलब्ध कराने कहा

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर।

कलेक्टर अजीत वसंत ने मंगलवार को जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव के साथ राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

संबद्ध चिकित्सालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय के विभिन्न विभागों, निर्माण कार्यों, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता तथा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। मरीजों की सुविधा हेतु मेडिकल कॉलेज में नेत्र प्रत्यारोपण हेतु तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में सीपेज की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम को 50 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है, इसका टेंडर फायनल हो गया है।

इस दौरान कलेक्टर ने सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा चिकित्सालय के बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज एरिया के अपूर्ण निर्माण कार्य का अवलोकन करते हुए, शेष राशि आर.ई.एस. को हस्तांतरित कर कार्य पूर्ण कराने कहा। इसी प्रकार निर्माणाधीन स्टोर रूम, गार्ड रूम, शौचालय सहित अन्य कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। विद्युत व्यवस्था की समीक्षा करते हुए



जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

जिले में नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 09 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस हेतु कलेक्टर अजीत वसंत ने अस्पताल परिसर से जागरूकता रैली को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। रैली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। रैली के माध्यम से लोगों को नेत्रदान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। निरीक्षण के दौरान मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अविनाश मैश्रम, अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर. सी. आर्या, सिविल सर्जन डॉ. जे. के. रेलवानी सहित चिकित्सालय के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने पावर ऑडिट के अनुरूप विद्युत अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन का चिकित्सालय स्तर पर पुनः मूल्यांकन कर अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस हेतु पीडब्ल्यूडी एवं सीएसपीडीसीएल को बजट उपलब्ध कराने कहा। साथ ही 150 के.व्ही.ए. नवीन ट्रांसफार्मर की स्थापना के संबंध में प्राक्कलन प्राप्त करने कहा गया। कलेक्टर ने पोषण पुनर्वास केन्द्र में सीपेज प्रबंधन एवं उन्नयन से संबंधित कार्य आर.ई.एस. के माध्यम से तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला शीघ्र हस्तक्षेप केन्द्र (डी.ई.आई.सी.) अम्बिकापुर के प्रथम तल में निर्माणाधीन विभिन्न वार्डों के लिए स्लैब निर्माण संबंधी प्राक्कलन प्रस्तुत करने आर.ई.एस. के उप अभियंता को कहा। वहीं एम.सी.एच. भवन में ड्रेनेज रिपेयर एवं मरम्मत हेतु आर.ई.एस. को स्वीकृत कार्य को तत्काल प्रारंभ कराने, चिकित्सालय की स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी शौचालयों, वार्डों एवं पूरे परिसर की नियमित एवं बेहतर सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लेबर वार्ड एवं पी.एन.सी. वार्ड के बीच कनेक्टिंग पैसेज में हो रहे सीपेज की समस्या का अवलोकन कर नगर निगम को शीघ्र सीपेज रोकने हेतु कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

‘नन्हे कंधों पर कांवड़, हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा उदयपुर’

स्कायरिच स्कूल की पहल: भगवा वस्त्रों में दिखे नन्हे शिवभक्त

छ.ग.फ्रंटलाइन उदयपुर।

सावन के अंतिम सोमवार को स्कायरिच एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा एक अनूठी बाल कांवड़ यात्रा निकाली गई। केजी-1 से कक्षा पांचवीं तक के सैकड़ों विद्यार्थी भगवा वस्त्र धारण कर कांवड़ लेकर उद्देश्वर शिवमंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। यात्रा का शुभारंभ विद्यालय परिसर में गायत्री साधक शुभलाल राजवाड़े, मूरितराम कौशिक और सतीश सोनी के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुआ। विद्यालय के प्राचार्य रामप्रसाद गुप्ता एवं अभिभावकों के नेतृत्व में बच्चे ‘हर-हर महादेव, बोल बम’ के जयघोष करते हुए नगर भ्रमण पर निकले। नगर में जगह-जगह बाल कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। व्यवसायी बाबूराम अग्रवाल,



जिमी अग्रवाल, शिवकुमार सिंह सोनी परिवार, पप्पू जनरल सोनी, हिंदू सिंह सोनी सहित स्टोर और मुस्कान ज्वेलर्स की

भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जुड़े बच्चे

प्राचार्य रामप्रसाद गुप्ता ने कहा कि आयोजन का उद्देश्य बच्चों को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोड़ना है। उप सरपंच शेखर सिंहदेव और कल्पना भदौरिया ने भी विद्यालय के इस पहल की सराहना की। इस सफल आयोजन में विद्यालय प्रबंधक श्यामा चरण गुप्ता, सोहणा मोबाइल, रोशन अग्रवाल परिवार, आकांक्षा ड्रेसेस, सूरज यादव सहित समस्त शिक्षक, अभिभावक और नगरवासियों का सराहनीय योगदान रहा।

और से बच्चों को फल, बिस्किट, पानी, लीची और प्रसाद वितरित किया गया। शारदा महिला मंडल और मनीष बंसल ट्रैक्टरर्स ने भी विशेष व्यवस्था कर बच्चों का उसाह बढ़ाया।

उदयपुर में पहली बार आयोजित इस यात्रा को देखने बड़ी संख्या में नगरवासी उमड़े। नन्हे बच्चों का कांवड़ लेकर चलना आकर्षण का केंद्र रहा। मंदिर पहुंचकर सभी बच्चों ने विधि-विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिवार और समाज की सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में उप सरपंच शेखर सिंहदेव, मंडल उपाध्यक्ष मनीष बंसल, शारदा महिला मंडल से कल्पना भदौरिया, बसंत सिंह, कन्हई राम बंजारा सहित गणमान्य नागरिक, शिक्षक और बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।

वृत्त स्तरीय वन संरक्षण ऑनलाइन कार्यशाला संपन्न

छ.ग.फ्रंटलाइन अम्बिकापुर।

वृत्त स्तरीय वन संरक्षण ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को काष्ठगार में किया गया। कार्यशाला में रायपुर से सहायक वन संरक्षक संदीप सिंह तथा एफएमआईएस टीम के द्वारा उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन ऐप के माध्यम से ऐप का उपयोग एवं कार्यप्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ सरगुजा के वनमण्डलाधिकारी लोकाथ पटेल द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

(बालाजी क्लीनिक)

मद्रासी दवाखाना

Reg. No. Cg03026

ISO 9001: 2015 CERTIFIED

बादी एवं सूखी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।

समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा

बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

डॉ. के.एम. राव

एम.एस.(आयु) शल्य

भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग

शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद

कोटबहरा जंगल में पेड़ से लटके मिले प्रेमी युगल के शव

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। ग्राम पंचायत कल्याणपुर के कोटबहरा जंगल में मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब जंगल के भीतर एक पेड़ पर गमछे के सहारे युवक-युवती के शव लटके मिले। दोनों की पहचान 18 वर्षीय रिकी कुमारी पिता अमरजीत सिंह निवासी तेलसरा थाना रामानुजनगर और 21 वर्षीय मूलचंद पिता मोहरलाल निवासी खड़गवां प्रतापपुर के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलते ही लटोरी पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि मंगलवार को आसपास के कुछ ग्रामीण खुखड़ी चुनने के लिए कोटबहरा जंगल की ओर गए थे। जंगल के अंदर पहुंचने पर उनकी नजर पेड़ से लटके युवक-युवती पर पड़ी। यह दृश्य देखते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस

को दी। सूचना मिलते ही लटोरी पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मौजूदगी में घटनास्थल की जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों शवों को पेड़ से नीचे उतरवाकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को भी जांच के लिए सुरक्षित किया गया है। शवों की पहचान पुलिस के लिए शुरुआती चुनौती थी। जांच के दौरान

युवक की जेब से आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर उसकी पहचान मूलचंद के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने

के साथ युवती को कई बार घूमते हुए देखने की बात कही है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल के समीप पुलिस

इस संबंध में पुलिस ने अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। परिजनों के मुताबिक दोनों सोमवार को अपने-अपने घर

वास्तविक कारणों को लेकर सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल की स्थिति, दोनों के मोबाइल फोन, परिजनों एवं परिचितों से पूछताछ तथा अन्य परिस्थितियन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों के संबंध में स्पष्ट स्थिति सामने आ सकेगी। फिलहाल लटोरी पुलिस ने मार्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पंचनामा एवं जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम उपरांत शव परिजनों को सौंप दिए हैं। घटना के बाद दोनों परिवारों में शोक का माहौल है, वहीं जंगल में एक साथ युवक-युवती के शव मिलने की घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का दौर जारी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और परिजनों से पूछताछ के आधार पर ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।

राखी के धागे में विश्वास अपार, बहनों के साथ विष्णु भैया की सरकार

★ राखी से पहले भैया का बहनों को शगुन
★ महतारी वंदन की 31वीं किस्त से प्रमिला के चेहरे पर आई मुस्कान

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। रक्षाबंधन का पर्व आते ही बहनों की खुशियां अपने आप बढ़ जाती हैं। भाई की कलाई पर राखी बांधने और उनके लिए मिठाई लाने की तैयारियों के बीच अगर मायके से शगुन मिल जाए, तो त्योहार हमें जो शगुन और भी खास हो जाती है। वि.क।स.ख.ण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत भनौरा निवासी श्रीमती प्रमिला विश्वकर्मा के लिए इस रक्षाबंधन ऐसा ही शगुन लेकर आया महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त का खेह।

राखी से पहले मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी की, जिससे प्रदेश की लाखों महिलाओं के खातों में आर्थिक सहायता राशि पहुंची। प्रमिला के लिए यह राशि सिर्फ आर्थिक संबल नहीं, बल्कि रक्षाबंधन के मौके पर भाई के लिए राखी और मिठाई खरीदने का सहारा बन गई। महतारी वंदन योजना के तहत प्रमिला को हर महीने 1 हजार रुपये की सहायता राशि मिलती है। अब तक उन्हें 30 हजार रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है। श्रीमती प्रमिला बताती हैं कि रक्षाबंधन के ठीक पहले मिली यह राशि उनके लिए बेहद खास है। वह इसी राशि से अपने भाई के लिए राखी और मिठाई

खरीदकर पूरे उत्साह के साथ पर्व मनाएंगी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को आत्मीयता से विष्णु भैया कहते हुए प्रमिला के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। वह कहती हैं कि भैया, रक्षाबंधन के अवसर पर आपने हमें जो शगुन दिया है, वह हमारे लिए बहुत खास है। इस राशि से मैं अपने भाई के लिए राखी और मिठाई खरीदूंगी। इस स्नेह और सहयोग के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती प्रमिला खुशी जाहिर करते हुए बताती हैं कि महतारी वंदन योजना की राशि रक्षाबंधन से पहले मिली यह शगुन बहनों के लिए आर्थिक मजबूती के साथ अपनत्व और सम्मान का एहसास भी लेकर आया है और इस रक्षाबंधन, बहनों के चेहरे पर मुस्कान है और प्रमिला की मुस्कान में महतारी वंदन योजना के उस बदलाव की झलक दिखाई देती है, जहां हर महीने मिलने वाली सहायता राशि महिलाओं के लिए केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि अपनी जरूरतें पूरी करने, छोटे-छोटे सपने संवराने और त्योहारों को पूरे उत्साह से मनाने का माध्यम बन रही है। इस रक्षाबंधन महतारी वंदन की राशि ने प्रमिला के लिए खुशियों में एक नया रंग भर दिया है।

मेमू ट्रेन की चपेट में आने से ग्रामीण की हुई मौत

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। अंबिकापुर-अनूपपुर रेल पथ पर सोमवार की शाम 50 वर्षीय एक ग्रामीण की मेमू ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई है। विश्रामपुर पुलिस ने बताया कि अंबिकापुर-अनूपपुर मेमू गाड़ी संख्या 68758 अंबिकापुर से अनूपपुर के लिए खाना हुई थी। तभी रात्रि करीब साढ़े नौ बजे पटरी पार करने के दौरान 50 वर्षीय अतवार सिंह पिता देवसाय मेमू ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि ग्रामीण शराब पीने का आदी था और उसका घर रेल पटरी के करीब था। अनुमान लगाया जा रहा है कि वह नशे की हालत में रेल पटरी पार कर रहा होगा, इसी दौरान वह मेमू ट्रेन की चपेट में आ गया होगा। घटना कुमदा बस्ती ढोडगापाड़ा रेलवे पोल 1017/212-213 के पास की बताई जा रही है। सूचना पर विश्रामपुर पुलिस ने सब पंचनामा पीएम उपरांत शव परिजन के सुपुर्द कर मामले में मार्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है।

गणेशपुर में तिल फसल पर कृषक खेत पाठशाला का आयोजन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। आत्मा योजनांतर्गत कृषक खेत पाठशाला का आयोजन ग्राम पंचायत गणेशपुर में तिल फसल के विषय पर किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र अजिरमा से वैज्ञानिक डॉ. ज्ञानेन्द्र कुमार एवं वीरेन्द्र कुमार, कार्यक्रम सहायक तथा श्रीमती रामरती पैकरा उपस्थित रहे। कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को तिल फसल की सफल खेती के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान तिल की खेती के लिए

उपयुक्त जलवायु, मिट्टी का चयन, खेत में जल निकास, बीज

विभिन्न कृषि तकनीकों के बारे में किसानों को समझाया गया।

उत्पादकता एवं गुणवत्ता बढ़ाने का आह्वान किया कार्यक्रम के दौरान किसानों ने खेती से संबंधित विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका कृषि विशेषज्ञों द्वारा समाधान एवं आवश्यक सुझाव दिए गए। कार्यक्रम में आत्मा योजना से एटीएम बिन्दुमती पैकरा एवं कृषक मित्र सहित ग्राम के कृषक उपस्थित रहे। कृषक खेत पाठशाला के माध्यम से किसानों को आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी देकर बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया।



की उचित गहराई, सिंचाई तथा उर्वरक के संतुलित उपयोग सहित

विशेषज्ञों ने किसानों से वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर तिल फसल की

शासकीय महाविद्यालय सिलफिली में हरिशंकर परसाई जयंती पर व्यंग्य और सामाजिक सरोकारों पर हुई सार्थक चर्चा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। शासकीय महाविद्यालय सिलफिली में हरिशंकर परसाई जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्री बुजलाल साहू प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय सूरजपुर के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विशिष्ट अतिथि श्री संदीप सोनी, सहायक प्राध्यापक शासकीय कन्या महाविद्यालय सूरजपुर रहे। इसके साथ ही कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि तथा महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों द्वारा संस्कृति की देवी माँ सरस्वती के छायाचित्र पर दीप और धूप प्रज्वलन से हुआ। सर्वप्रथम महाविद्यालय की छात्राओं अनामिका तथा मीनाक्षी ने हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त जीवन तथा साहित्यिक परिचय प्रस्तुत किया। बी.ए. प्रथम सेमेस्टर के छात्र प्रियांशु ने परसाई के व्यंग्य “शिकायत मुझे भी है” का पाठ कर विद्यार्थियों को देश से पलायन कर रहे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, डॉक्टरों की विडंबना के साथ तथा शासन-प्रशासन की बेरोजगारों के प्रति उदासीनता के भाव से अवगत कराया। छात्रा सोनम ने परसाई के व्यंग्य “चूहा और मैं” का पाठ कर देश के लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता की आशा व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान हरिशंकर परसाई के जीवन पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा निर्मित शैक्षिक वीडियो को प्रोजेक्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्य अतिथि श्री बुजलाल साहू ने विद्यार्थियों को अजिंथा, लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्ति को समझाते हुए व्यंग्य से उसके संबंध को बताया। उन्होंने कहा कि परसाई की

समाज के लिए चिंता हमें यह संदेश देती है कि हमें समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझना चाहिए। हमें समाज के दोहरे चरित्र को भी समझने की आवश्यकता है, जहाँ उसकी



कथनी और करनी दोनों में फर्क है। हमें अपने स्वत्व से ऊपर उठकर समाज और देश के लिए योगदान देना चाहिए। जब हम समाज के विषय में सोचना शुरू करेंगे तभी हमें उसमें मौजूद विभिन्न बुराइयों से साक्षात्कार होगा और हम उनके विरुद्ध आवाज उठा सकेंगे। भारतेन्दु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, ज्ञान चतुर्वेदी इत्यादि की रचनाएं हमें समाज के प्रति चिंतन के लिए विवश करती हैं। साहित्य की हर विधा कोई न कोई संदेश देती है और हमें अकेला होने नहीं देती इसलिए अच्छा साहित्य अवश्य पढ़ना चाहिए। महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ अजय कुमार तिवारी ने बताया कि परसाई कबीर के एक प्रिय दोहे “सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे” को अक्सर गुनगुनाते थे। वे समाज के सच्चे पहरेदार थे। परसाई का जागरण समाज की भलाई के लिए था। परसाई ने समाज के सुनहरे पक्ष के पीछे छिपी कुरूपता को अपने व्यंग्य के माध्यम से

प्रस्तुत किया। हरिशंकर परसाई का व्यक्तित्व कबीर की तरह था। उन्होंने “कागद की लेखी” पर नहीं बल्कि “आँखन देखी” पर विश्वास किया। उन्होंने समाज के मध्य

है। हरिशंकर परसाई आचरण और जीवन मूल्य को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हैं। इस देश में मानव मूल्यों के पतन का कारण मध्यक और शासन की गलत नीतियों को

मानते हैं। इस कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक श्री आशीष कौशिक ने सभी को धन्यवाद देकर कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान सहायक प्राध्यापक डॉ प्रेमलता एक्का, श्रीमती अंजना, श्री जफरी, श्री संजय कुमार तथा कार्यालयीन कर्मचारी के साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे।

25 किसानों का फौती नामांतरण के साथ एग्रीस्टेक पंजीयन बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में जिले में किसानों को शासकीय योजनाओं को लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने तथा राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। साथ ही शिविर लगाकर एग्रीस्टेक पंजीयन का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत लावा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

साढ़े 8 क्विंटल गांजा तस्करी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर सिलफिली में करीब साढ़े 8 क्विंटल गांजा जब्त की बहुचर्चित मामले में जयनगर पुलिस ने एक और फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने मध्यप्रदेश के कटनी जिले में दबिश देकर ग्राम खीरहनी निवासी 39 वर्षीय जाजोन पारधी पिता कदम पारधी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है पुलिस के अनुसार गत दिनों 4 जून को सिलफिली में ग्रामीणों की मदद से एक सवारी बस में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर ले जाने की सूचना सामने आई थी। सूचना के बाद जयनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बस की तलाशी ली, जिसमें करीब 8 क्विंटल 50 किलो गांजा बरामद हुआ था। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। मामले में पुलिस ने बस चालक सहित छह महिलाओं को पहले ही गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया था।

पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल के मार्गदर्शन में जयनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ में गांजा तस्करी के नेटवर्क को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने की बात



कही गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी करीब ढाई माह पूर्व अपने साथियों के साथ उड़ीसा गया था। वहां से उसके साथी पिकअप वाहन में गांजा लेकर अंबिकापुर पहुंचे थे। इसके बाद गांजे को एक सवारी बस में लोड कर मध्यप्रदेश के विजयराघोगढ़ ले जाने की तैयारी थी, लेकिन तस्करों की यह योजना सिलफिली में पुलिस की कार्रवाई के बाद धरी

की धरी रह गई। ग्रामीणों की मदद से पुलिस तक सूचना पहुंची और बस की जांच के दौरान गांजे की बड़ी खेप बरामद कर ली गई। मामले में फरार चल रहे जाजोन पारधी

की तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। उसके कटनी जिले के बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खीरहनी में होने की जानकारी मिलने के बाद जयनगर पुलिस की टीम ने वहां दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से गांजा तस्करी से जुड़े अन्य फरार आरोपियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि साढ़े 8 क्विंटल गांजा बरामद

होने के बाद पुलिस ने मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन तस्करी के इस बड़े नेटवर्क का मुख्य आरोपी समेत करीब आधा दर्जन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्तार से बाहर हैं। पुलिस इनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश देने के साथ ही मामले से जुड़े लोगों की जानकारी जुटा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद होने से यह मामला केवल एक खेप की तस्करी तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि पुलिस अब इसके पीछे सक्रिय पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर तस्करी के स्रोत, परिवहन व्यवस्था और गांजे को खपाने वाले लोगों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। कार्रवाई में जयनगर थाना प्रभारी उपनिरीक्षक अमित गुप्ता, उपनिरीक्षक सोहन सिंह, प्रधान आरक्षक राजेंद्र एक्का, आरक्षक हरिशंकर, जितेंद्र साहू सहित पुलिस टीम सक्रिय रही। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास जारी हैं।

निधन चरणजीत गिल

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन बिश्रामपुर। नगर पंचायत शिवनंदनपुर के शांतिनगर निवासी मुखतार सिंह गिल के पुत्र चरणजीत सिंह गिल का निधन हो गया। वे 34 वर्ष के थे। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे, सोमवार की रात सांस लेने में तकलीफ होने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, बुधवार को अंतिम संस्कार किया जायेगा।



गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत लावा में पीएम किसान

प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ की गई। इनमें से 25 किसानों का फौती नामांतरण पूर्ण

शिक्षकों का शक्ति प्रदर्शन पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में गूंजा विरोध

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बलरामपुर। शिक्षक संवर्ग की विभिन्न समस्याओं के निराकरण और लॉबित मांगों की पूर्ति को लेकर मंगलवार को जिला मुख्यालय में शिक्षकों का बड़ा आंदोलन देखने को मिला। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले जिलेभर से हजारों की संख्या में शिक्षक जिला मुख्यालय के साप्ताहिक बाजार स्थल पर एकत्रित हुए। यहां से शिक्षकों ने विशाल रैली निकालकर अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों के आंदोलन का असर जिले के शैक्षणिक संस्थानों में भी देखने को मिला। आंदोलन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अवकाश लिया,



जिसके कारण जिले के कई स्कूलों में ताले लटके रहे और शैक्षणिक कार्य प्रभावित हुआ। जिले के विभिन्न विकासखंडों से शिक्षक बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचे थे।

टेट की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग

ज्ञापन में शिक्षक संवर्ग के लिए टेट की अनिवार्यता समाप्त करते हुए उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित

करने की मांग की गई। मोर्चा का कहना है कि माननीय न्यायालय द्वारा टेट के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है, ऐसे में सभी पदोन्नतियों में टेट की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए।

पूर्व सेवा गणना और पुरानी पेंशन की मांग

शिक्षकों ने शिक्षक एलबी संवर्ग की पंचायत संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना किए जाने तथा पूर्ण पुरानी पेंशन सहित शिक्षा विभाग में लागू सभी लाभ प्रदान करने की मांग रखी। इसके साथ ही समस्त शिक्षक संवर्ग की लॉबित वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए केंद्रीय वेतनमान संरचना के आधार पर वेतन

निर्धारण करने की मांग भी की गई।

राजपत्र में संशोधन और ब्रिज कोर्स की मांग

ज्ञापन में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम के 13 फरवरी 2026 के राजपत्र में एलबी संवर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन करने की मांग की गई। वहीं बीएड शिक्षक संवर्ग के लिए शिक्षा विभाग द्वारा योजना बनाकर ब्रिज कोर्स के माध्यम से उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने की भी मांग की गई। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला संचालक उपेंद्र सिंह एवं पवन सिंह ने कहा कि शिक्षक संवर्ग की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का शीघ्र निराकरण आवश्यक है।



उसकी दोस्त सिमरन नेताम ने परिजनों को सूचना दी कि रायपुरा अस्पताल और सुमीत बाजार के पास कैलाश पर हमला हुआ है। आरोप है कि चंगोराभाठा निवासी टिकेन्द्र देवांगन उर्फ बाउ अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से पहुंचा और चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे लेकिन कैलाश वहां नहीं मिला। कुछ देर बाद वह गंभीर हालत में खुद घर पहुंचा। परिजनों ने देखा कि पेट में चाकू लगने से

गंभीर चोट आई थी। परिजनों ने तुरंत डायल-112 को सूचना दी और एम्बुलेंस से उसे एम्स रायपुर में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है।

पुलिस ने दर्ज किया केस

घटना की सूचना पर 24 अगस्त सुबह 8:35 बजे डीडी नगर थाने के एएसआई गुलाब सिन्हा एम्स पहुंचे और पिता भोजोराम का बयान दर्ज किया।

मिलाई नगर चुनाव विवाद, देवेंद्र यादव की एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में खारिज

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। भिलाई नगर विधानसभा चुनाव विवाद में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 30 जून के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी एसएलपी खारिज कर दी है। इसके साथ ही चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में नियमित ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है।

क्या है पूरा मामला?

2023 के विधानसभा चुनाव में भिलाई नगर सीट क्रमांक-65 से देवेंद्र



यादव के निर्वाचन को पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका क्रमांक 9/2024 में आरोप लगाया गया है कि नामांकन के दौरान दाखिल शपथ-पत्र में वैधानिक जानकारी का समुचित खुलासा नहीं किया गया। याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 से जुड़े कानूनी सवाल भी उठाए गए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर मुद्दा क्रमांक 2 और 4 को

प्रारंभिक मुद्दों के रूप में तय कर ट्रायल से पहले फैसला करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने 30 जून 2026 को मांग खारिज करते हुए कहा था कि ये मुद्दे केवल कानून के सवाल नहीं हैं, बल्कि तथ्य और कानून दोनों से जुड़े हैं। इसलिए इनका फैसला साक्ष्य आने के बाद ट्रायल के दौरान ही होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दखल से किया इनकार

इसी आदेश के खिलाफ देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी (सिविल) नंबर 28778/2026 दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया और

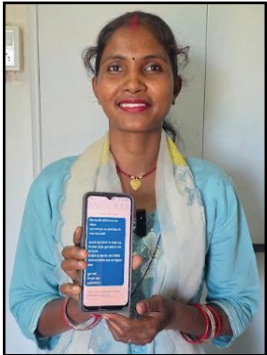
एसएलपी खारिज कर दी। अब हाईकोर्ट में दोनों पक्षों को अपने दावों के समर्थन में दस्तावेज और साक्ष्य पेश करने होंगे। गवाहों की परीक्षा और प्रतिपरीक्षा होगी।

दूसरी बार खारिज हुई एसएलपी

यह दूसरा मौका है जब इस मामले में देवेंद्र यादव की एसएलपी खारिज हुई है। इससे पहले आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज कराने की मांग वाली एसएलपी नंबर 6306/2025 को सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी को खारिज किया था।

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को मिल रही नियमित आर्थिक सहायता उनके लिए आर्थिक संबल का आधार बन रही है। योजना के तहत प्राप्त राशि से महिलाएं अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ पर्व एवं त्योहार भी उत्साहपूर्वक मना रही हैं। रक्षाबंधन पर्व से पहले योजना की 31वीं किस्त मिलने से लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत झुमरपारा की रहने वाली सरिता राजवाड़े के परिवार में भी खुशी



का माहौल है। सरिता राजवाड़े ने बताया कि महतारी वंदन योजना के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भैया द्वारा 31वीं किस्त की राशि जारी किए जाने से उन्हें बहुत खुशी हुई है। रक्षाबंधन जैसे पर्व से पहले

आर्थिक सहायता मिलने से अब वे अपने भाई के लिए राखी, मिठाई और उपहार खरीदकर त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मना सकेंगी। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। महतारी वंदन योजना की राशि मिलने से इस बार वे भी अपने भाई के लिए अपनी पसंद की राखी और मिठाई खरीद सकेंगी तथा उन्हें उपहार भेंट कर सकेंगी। उनके लिए यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि

त्योहार की खुशियों को और बेहतर ढंग से मनाने का अवसर भी लेकर आई है। सरिता राजवाड़े ने कहा कि योजना से मिलने वाली राशि परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भी मददगार साबित हो रही है। इससे उन्हें परिवार के बच्चों के पालन-पोषण, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में सहूलियत मिल रही है। नियमित रूप से मिलने वाली सहायता राशि से परिवार के खर्चों को व्यवस्थित करने में मदद मिलती है और छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा मिलता है।

राखी का बंधन, खुशियों का संसार-महतारी वंदन से बहनों को संबल अपार

महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त ने बढ़ाई रक्षाबंधन की खुशियां, बहनों को मिला आर्थिक संबल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता राशि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उनके पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को निभाने में भी सहायता प्रदान कर रही है। रक्षाबंधन जैसे पवन पर्व पर यह योजना बहनों के लिए विशेष

खुशियां लेकर आई है।

लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत लटोरी निवासी ममता राजवाड़े महिमा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं तथा जेंडर गतिविधियों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत उन्हें नियमित रूप से प्रतिमाह एक हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त होती है। योजना की 31वीं किस्त समय पर मिलने से इस वर्ष रक्षाबंधन का उत्साह और भी बढ़ गया है। ममता राजवाड़े कहती हैं कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का पर्व है।



महतारी वंदन योजना से प्राप्त राशि ने इस पर्व की तैयारियों को आसान बना दिया है। समय पर किस्त मिलने से वे अपने भाई के लिए राखी, मिठाई एवं अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर सकी हैं। इससे परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक भार भी नहीं पड़ा और

त्योहार की खुशियां दोगुनी हो गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई यह योजना उनके जैसे हजारों परिवारों के लिए सहारा बनी है। प्रतिमाह मिलने वाली राशि से महिलाएं अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में भी योगदान दे रही हैं। ममता राजवाड़े ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को अपना विष्णु भैया बताते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन से पहले

महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त प्राप्त होना बहनों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। इससे महिलाओं को आत्मविश्वास मिला है और वे सम्मानपूर्वक अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर पा रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का धन्यवाद करते हुए कहा कि महिलाओं के हित में संचालित यह योजना उनके जीवन में खुशहाली लेकर आई है। रक्षाबंधन के अवसर पर मिली यह आर्थिक सहायता बहनों के लिए सरकार की संवेदनशील सोच और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है।

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में यूथ कांग्रेस चुनाव के बीच गुटबाजी का असर एनएसयूआई पर भी दिखने लगा है। यूथ कांग्रेस चुनाव को लेकर एनएसयूआई के 5 जिलों में की गई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है।

क्या है पूरा मामला?

एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडेय ने 20 अगस्त को पांच जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का आदेश जारी किया था। इसमें रंजेश सिंह क्षत्री को



बिलासपुर ग्रामीण, समर्थ मिरानी को बिलासपुर शहर, दुर्गात आर्या को मुंगेली, उस्मान रजा को बालोद और रोशन सिंह ठाकुर को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। आरोप है कि बिलासपुर एनएसयूआई

जिलाध्यक्ष रंजित सिंह भुषेण बघेल गुट के यूथ कांग्रेस प्रत्याशी सत्येंद्र चेलक के लिए प्रचार कर रहे थे। इसकी शिकायत संगठन के बड़े पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय कार्यालय में की, जिसके बाद आनन-फानन में नई नियुक्तियां कर दी गईं।

कलेक्टर का भैयाथान में सघन औचक निरीक्षण, जमीनी हकीकत परखी, फरियादियों से किया सीधा संवाद

तहसील से अस्पताल और जनपद तक पहुंचीं कलेक्टर, लापरवाही पर जताई नाराजगी, त्वरित निराकरण और व्यवस्था सुधार के दिए सख्त निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

भैयाथान। सूरजपुर जिले के विकासखंड मुख्यालय भैयाथान में मंगलवार को उस समय प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया, जब कलेक्टर रेना जमील बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण पर पहुंच गईं। सुबह से ही विभिन्न शासकीय कार्यालयों का सघन निरीक्षण कर कलेक्टर ने न केवल फाइलों में चल रहे कामकाज को परखा, बल्कि जमीन पर आम जनता को मिल रही सुविधाओं की हकीकत भी जानी। कलेक्टर ने एक-एक कर एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, नायब तहसीलदार न्यायालय, रिकॉर्ड रूम, लोक सेवा केंद्र, जनपद पंचायत कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मनरेगा शाखा का निरीक्षण किया।

हर कार्यालय में उन्होंने उपस्थिति पंजी से लेकर प्रकरणों के निराकरण की स्थिति तक की बारीकी से जांच की।

न्यायालय में फरियादियों से सीधा संवाद, बोली-चक्कर नहीं लगवाओ

तहसील न्यायालय के निरीक्षण के दौरान सबसे अहम नजारा देखने को मिला। वहां अपनी जमीन, नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व मामलों को लेकर हजारों फरियादियों से कलेक्टर खुद जाकर मिलीं। उन्होंने एक-एक फरियादी को बैठाकर उसकी समस्या सुनी। कई फरियादियों ने बताया कि उनके मामले महीनों से लंबित हैं। इस पर कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से फाइल मंगवाई और प्रकरण की

अद्यतन स्थिति पूछी। उन्होंने दो टुक कहा कि आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाना पड़ रहा है, यह ठीक नहीं है। सभी पात्र प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए और लोगों को उनकी पात्रता के अनुसार शासन की सेवाओं का लाभ तुरंत मिले।

लोक सेवा केंद्र में आधार सेवा की पड़ताल, महिलाओं से पूछी परेशानी

इसके बाद कलेक्टर लोक सेवा केंद्र पहुंचीं। यहां आधार कार्ड बनवाने और आधार में सुधार कराने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, बुजुर्ग और महिलाएं कतार में खड़ी थीं। कलेक्टर ने उनसे सीधे पूछा कि क्या उन्हें समय



पर टोकन मिल रहा है, क्या सर्वर या अन्य कोई परेशानी आ रही है और क्या किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क तो नहीं लिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सर्वर डाउन होने से पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। इस पर कलेक्टर ने लोक सेवा केंद्र के ऑपरेटरों को निर्देश दिया कि आधार से संबंधित सभी सेवाओं को निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा में पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीणों को अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा कि

लोक सेवा केंद्र शासन और जनता के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, यहां की व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए।

तहसील परिसर में गूंजी महिला शौचालय की मांग

निरीक्षण के दौरान ही तहसील परिसर में अधिवक्ता एपी दास ने कलेक्टर के समक्ष एक महत्वपूर्ण मांग रखी। उन्होंने बताया कि तहसील कार्यालय में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में पशुकार आते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं

भी होती हैं, लेकिन परिसर में उनके लिए अलग से महिला शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कलेक्टर ने इस मांग को गंभीरता से सुना और संबंधित विभाग को जल्द प्रस्ताव तैयार कर शौचालय निर्माण की कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अस्पताल में मरीजों से पूछा - इलाज कैसा मिल रहा है?

दोपहर में कलेक्टर अचानक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैयाथान पहुंच गईं। उन्होंने वार्डों में जाकर भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना। मरीजों से पूछा कि डॉक्टर समय पर देख रहे हैं या नहीं, दवाइयां अस्पताल से मिल रही हैं

या बाहर से लेनी पड़ रही है, जांच की सुविधा कैसी है। मरीजों से फीडबैक लेने के बाद उन्होंने बीएमओ डॉ. राकेश सिंह और उपस्थित चिकित्सकों को निर्देश दिया कि अस्पताल में आने वाले हर मरीज का संवेदनशीलता के साथ उचित उपचार हो। अस्पताल में साफ-सफाई, दवा वितरण और स्टॉफ की उपस्थिति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संस्थागत प्रसव और मौसमी बीमारियों के मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था रखने को भी कहा।

जनपद में गंदगी देखकर नाराज हुई कलेक्टर

जनपद पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परिसर और कार्यालय कक्षों में साफ-सफाई की कमी पर नाराजगी

जाहिर की। उन्होंने कहा कि जब सरकारी कार्यालय ही साफ नहीं होंगे तो आम लोगों में स्वच्छता का संदेश कैसे जाएगा। उन्होंने जनपद सीईओ विनय गुप्ता को निर्देश दिया कि कार्यालय परिसर में नियमित साफ-सफाई, पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों को बेहतर माहौल मिल सके। इसके अलावा उन्होंने रिकॉर्ड रूम में पुराने दस्तावेजों के रखरखाव और व्यवस्थित संधारण का जायजा लिया और मनरेगा कार्यालय में आनन-फानन में नई नियुक्तियां कर दी गईं।

अब अंतरिक्ष में खुलेंगे संभावनाओं के नए द्वार

भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल रॉकेट लॉन्च करने और उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने तक सीमित नहीं रह गई है। देश का निजी स्पेस सेक्टर ऐसी तकनीकों पर काम कर रहा है, जो आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष की पूरी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल सकती हैं। सैटेलाइट रि-पयूजिंग, अंतरिक्ष का कचरा हटाने वाले रोबोट, माइक्रोग्रैविटी में दवाइयों का निर्माण और हर महीने रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी इस बदलाव के स्पष्ट संकेत हैं। यह भारत के लिए वैज्ञानिक उपलब्धि के साथ-साथ आर्थिक और रोजगार के नए अवसरों का भी द्वार खोल रहा है। भारत अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर बनने और पूरी स्पेस इकोनॉमी खड़ी करने की तैयारी में है। इससे आम आदमी से लेकर किसानों तक को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 20 स्पेस स्टार्टअप के प्रमुखों की बातचीत से यह भरोसा और मजबूत हुआ है कि भारत निजी क्षेत्र को अंतरिक्ष की नई दौड़ में बड़ी भूमिका देने के लिए तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय कंपनियां अब केवल मौजूदा तकनीक को दोहराने के बजाय भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर समाधान विकसित कर रही हैं। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को ईंधन देने की तकनीक इसका बड़ा उदाहरण है। अंतरिक्ष में बहुत मलबा पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती है। निष्क्रिय सैटेलाइट और अन्य अवशेष भविष्य के मिशनों के लिए खतरा बन सकते हैं। भारतीय स्टार्टअप का रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट के जरिये मृत सैटेलाइट को पकड़कर कक्षा से हटाने का प्रयास इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। यदि भारत इस तकनीक में सफल होता है तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्पेस सर्विस उपलब्ध कर सकता है। सबसे आकर्षक संभावनाओं में अंतरिक्ष में दवाइयों का निर्माण है। माइक्रोग्रैविटी में कुछ प्रोटीन और जैविक पदार्थ धरती की तुलना में अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। ऐसे में अंतरिक्ष आधारित फार्मा उत्पादन भविष्य में नई दवाओं और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन के विकास में मदद कर सकता है। हर महीने एक रॉकेट लॉन्च करने का लक्ष्य पूरा होने पर भारत वैश्विक वाणिज्यिक लॉन्च बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। कम लागत, कुशल इंजीनियर और तेजी से विकसित होता स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत की प्रतिस्पर्धात्मक ताकत हैं। विदेशी कंपनियों से मिल रहे नए अनुबंध बताते हैं कि दुनिया भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी को गंभीरता से देख रही है। अंतरिक्ष तकनीक का लाभ धरती पर आम नागरिक और किसान तक पहुंचना भी जरूरी है। सैटेलाइट डेटा के माध्यम से मौसम, मिट्टी की नमी और फसल के स्वास्थ्य की सटीक जानकारी किसानों को मिल सकती है। आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, संचार, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का विस्तार जीवन को बेहतर बना सकता है। यदि लगभग 10 लाख किसानों तक इसका लाभ पहुंचता है तो अंतरिक्ष विज्ञान का सीधा सामाजिक-आर्थिक प्रभाव दिखाई देगा। कुल मिलाकर अंतरिक्ष की यह नई दौड़ भारत के लिए प्रतिष्ठा से कहीं अधिक आत्मनिर्भरता, रोजगार, नवाचार और आर्थिक विकास की दौड़ है। यदि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर इस अवसर को सही दिशा देते हैं तो अंतरिक्ष में खुल रहे ये नए द्वार भारत की धरती पर विकास की नई राह खोल सकते हैं और युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करावाएंगे।

मंथन

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा



विरोध प्रदर्शन करें, पर न

हो सीमाओं का अतिक्रमण

आए दिन होने वाले प्रदर्शनों के चलते सामान्य जनजीवन को बंधक बना देने की प्रवृत्ति पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि प्रदर्शनों के कारण कई बार तो जीवन-मरण तक के हालात पैदा हो जाते हैं। अन्य सब कारणों और परिणामों को थोड़ी देर के लिए अलग कर भी दिया जाए तो भी हालात यहां तक हो जाते हैं कि यातायात प्रभावित होने से तत्काल मेडिकल रिलिफ की आवश्यकता वाले बीमारों तक का जीवन संकट में पड़ जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र में अपनी बात कहने, अपनी बात रखने और अपना विरोध अंतिक्रमण के सबको अधिकार है। कहीं गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी होना चाहिए, पर इसका मतलब यह तो नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बात कहने के चक्कर में दूसरों को अपने सामान्य नागरिक अधिकारों से वंचित कर दें। विरोध प्रदर्शन के साथ ही दायित्व भी होता है। शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का विरोध भी नहीं होता, पर कब इस तरह के प्रदर्शन हिंसक हो जाते हैं और कानून व्यवस्था के गंभीर हालात हो जाते हैं, इसका खामियाजा प्रदर्शनकारियों को नहीं अपितु प्रशासन और आमजन को भुगतना पड़ता है। सीजीपी के हालिया प्रदर्शनों के दौरान दिल्ली में जो हालात बने और जयपुर में पिछले दिनों सीजीपी द्वारा स्कूल प्रकरण को लेकर ग्रामवासियों और सीजीपी लोगों के साथ हालात बने, यह अपने आप में गंभीर हो जाता है। रॉंची और देश के अन्य स्थानों पर प्रदर्शनों को भी इसी संदर्भ में देखना होगा। शहर की सामान्य व्यवस्था को ही प्रभावित करने वाले स्थानों पर प्रदर्शन स्वीकृति पर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण हो जाती है कि शहर के बीच प्रदर्शन की अनुमति क्यों कर दी जानी चाहिए। दरअसल, सीजीपी द्वारा जंतर-मंतर पर प्रश्न किए गए और यह प्रदर्शन देखते-देखते हिंसक हो गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस प्रशासन और पक्ष-प्रतिपक्ष द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल जाता है, पर मूल कारण को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इससे पहले 2017-18 में जलकटू घटना के संदर्भ में गठित न्यायमूर्ति राजेश्वरन आयोग की सिफारिशों भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विरोध के चलते कानून हाथ में लेना या क्षेत्राधिकार से बाहर जाना एक मध्य समाज और सभ्य नागरिक की पहचान नहीं हो सकती। सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता।

एक बात यह भी समझनी होगी कि पुलिस प्रशासन भी आखिर आदमी है और देखा जाए तो उनका मरण दोनों तरफ से हो जाता है। यदि प्रदर्शनकारियों को एक सीमा से अधिक बढ़ने पर रोके नहीं तो प्रशासन की विफलता कहने में कोई देर नहीं लगाता, यहां तक कि प्रशासन की इंटेलिजेंस फेलियर जैसे आरोप लग जाते हैं। प्रदर्शन के हिंसक होने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की आलोचना आम हो जाती है, पर जब कई बार प्रदर्शनकारियों द्वारा बेरिफेड तोड़ने, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और निरपराध आमजन को निशाने पर लेने लगते हैं तो एक बात साफ हो जानी चाहिए कि फिर प्रशासन गुलाब के फूल देकर तो प्रदर्शन को नियंत्रित नहीं कर सकता। हालांकि प्रशासन को भी संयम बरतते हुए ही कदम उठाने चाहिए। दरअसल, तस्वीर के दोनों पक्षों को देखना होगा। यदि प्रदर्शन सामान्य होता है और अनुमति प्राप्त शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो तो उस पर पुलिस प्रशासन की सख्ती को किसी भी हालात में स्वीकारा नहीं जा सकता। प्रदर्शनकारियों द्वारा लक्ष्मण रेखा लांघी जाती है तो उस पर प्रशासन को भी कानूनी दायरे में रहते हुए कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी।

प्रशासन, प्रदर्शनकारियों और आमजन को अपनी सीमाओं को समझना होगा। सुविधों में बनने के लिए कदम उठाना किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। पहले तो प्रशासन को भी चाहिए कि प्रदर्शन आदि के लिए ऐसा स्थान निर्धारित हो, जहां से सामान्य जनजीवन किसी तरह से प्रभावित न हो सके। आम जन, शहरी यातायात, शहर का दैनिक जनजीवन किसी तरह से प्रभावित न हो। ऐसी व्यवस्था हो, जिससे प्रदर्शनकारियों की बात वे जहां पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंचाई जा सके। प्रदर्शनकारियों को भी प्रदर्शन के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। असामाजिक तत्वों को किसी तरह का मौका ही नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए दिल्ली उच्च न्यायालय व न्यायालयों द्वारा पूर्व में भी दी गई टिप्पणियों को गंभीरता से प्रदर्शनकर्ताओं और प्रशासन दोनों को समझना होगा व दोषारोपण के नाम पर जिम्मेदारी से भागने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दी जा सकती।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)



मुद्दा

डॉ. धनश्याम बादल

देश इस समय राजनीतिक

उबाल के ऐसे दौर से गुजर रहा

है, जहां मुद्दे कम और मुद्दों पर

मचा शोर अधिक दिखाई दे रहा

है। वंदे मातरम् को लेकर सत्ता

पक्ष और विपक्ष आमने- सामने

हैं और एक-दूसरे को राष्ट्रवादी

तथा राष्ट्रविरोधी साबित करने

की होड़ लगी है। दूसरी ओर,

परीक्षाओं में कथित धांधली और

अनियमितताओं के विरुद्ध

युवाओं का आक्रोश जंतर-मंतर

से लेकर झारखंड तक सड़कों

पर दिखाई दिया। भर्ती

परीक्षाओं को लेकर आंदोलन

इतना गंभीर हुआ कि केंद्रीय

शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना

पड़ा और अनेक परीक्षाएं रद्द

करनी पड़ीं। कई अन्य

परीक्षाओं की जांच का आदेश

हुआ। इसी बीच 2027 के

विधानसभा चुनावों की आहट ने

राजनीति का तापमान और बढ़ा

दिया है।

विचार

राजनीतिक द्वेष की आग में देश न जलाएं

देश इस समय राजनीतिक उबाल के ऐसे दौर से गुजर रहा है, जहां मुद्दे कम और मुद्दों पर मचा शोर अधिक दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम् को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं और एक-दूसरे को राष्ट्रवादी तथा राष्ट्रविरोधी साबित करने की होड़ लगी है। दूसरी ओर, परीक्षाओं में कथित धांधली और अनियमितताओं के विरुद्ध युवाओं का आक्रोश जंतर-मंतर से लेकर झारखंड तक सड़कों पर दिखाई दिया। भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन इतना गंभीर हुआ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ा और अनेक परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं। कई अन्य परीक्षाओं की जांच का आदेश हुआ। इसी बीच 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट ने राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच राजनीतिक टकराव हो या राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच तीखी बयानबाजी से लगता है, जैसे राजनीति ने संवाद की जगह संघर्ष को अपना स्थायी हथियार बना लिया है। यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं, लोकतांत्रिक विमर्श के लिए खतरे की घंटी है।

राहुल गांधी आज विपक्ष के सबसे मुखर चेहरों में हैं। छात्र आंदोलनों से लेकर सरकार की नीतियों तक वे लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। हाल में उन्होंने छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे तक की मांग की और बाद में पुलिस थाने के बाहर धरने के जरिए अपना विरोध दर्ज कराया। सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं है। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के इस तेवर को राजनीति और प्रचार का हथकंडा बताया। बेशक, विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है, लेकिन हर सवाल को राजनीतिक युद्ध में बदल देना भी स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। सत्ता का काम जवाब देना है, लेकिन आलोचक को राष्ट्रविरोधी मान लेना भी लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं। परिणाम यह है कि बहस अब अक्सर इस सवाल पर टिक जाती है कि कौन किसे कितना बड़ा देशभक्त या राष्ट्रविरोधी साबित कर सकता है, लेकिन जनता पूछ रही है- इस राजनीतिक युद्ध में उसके हिस्से में क्या आया? क्या बेरोजगार युवा को नौकरी मिली? क्या परीक्षा की तैयारी में लगाए गए उसके वर्षों का नुकसान वापस किया जा सकता है? क्या पेपर लीक या भर्ती में अनियमितता के आरोपों का स्थायी समाधान हुआ? क्या महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सवाल राजनीतिक प्राथमिकताओं के केंद्र में हैं? यही वे सवाल हैं जिनसे राजनीतिक विमर्श बार-बार भटकता दिखाई देता है। निःसंदेह वंदे मातरम् किसी दल की जागीर नहीं है। वह

भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की गौरवपूर्ण स्मृति है। उसका सम्मान हर भारतीय के लिए स्वाभाविक होना चाहिए। राष्ट्रीयता को राजनीतिक तलवार बनाकर विपक्ष को राष्ट्रविरोधी और सत्ता पक्ष को राष्ट्रवाद का अकेला ठेकेदार घोषित करना दोनों ही खतरनाक प्रवृत्तियां हैं। राष्ट्रवाद का प्रमाणपत्र संसद में बहस के दौरान नहीं बांटा जाना चाहिए। राष्ट्रभक्ति का अंतिम पैमाना यह नहीं हो सकता कि किसने कितनी जोर से नारा लगाया। देशभक्ति को किसी राजनीतिक दल के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, विपक्ष को भी यह समझना होगा कि सिर्फ सरकार के विरोध में आक्रामक



होना पर्याप्त नहीं है। राहुल गांधी और विपक्ष के सामने आज अवसर है कि वे युवाओं के वास्तविक प्रश्नों को राजनीतिक नारे से आगे ले जाकर ठोस नीति और वैकल्पिक कार्यक्रम में बदलें। सरकार पर आरोप लगाना आसान है; यह बताना कठिन है कि सत्ता में आने पर परीक्षा व्यवस्था को कैसे पारदर्शी बनाया जाएगा, रोजगार कैसे बढ़ाया जाएगा और प्रशासनिक जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी। इसी कसौटी पर विपक्ष की भी परीक्षा होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लिए भी यही कसौटी लागू होती है। लोकतंत्र में सरकार मजबूत होनी चाहिए, लेकिन असह्यति भी मजबूत होनी चाहिए।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का राजनीतिक संघर्ष आने वाले समय में और तीखा होना स्वाभाविक है। चुनावी राजनीति में एक-दूसरे की नीतियों की आलोचना होनी चाहिए, उपलब्धियों और विफलताओं पर बहस होनी चाहिए। लेकिन यदि चुनाव जीतने की रणनीति समाज को जाति, धर्म, क्षेत्र और राष्ट्रवाद की भावनात्मक रेखाओं में लगातार बांटने लगे तो चुनाव भले जीता जा सकता है, समाज नहीं। इसी तरह बाबा रामदेव हों या अरविंद

केजरीवाल, सार्वजनिक जीवन में प्रभाव रखने वाले हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि उसके शब्द केवल बयान नहीं होते, वे सामाजिक वातावरण भी बनाते हैं। इसलिए सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह आग में घी डालने के बजाय विवेक की आवाज बने। राजनीतिक दल यदि इस आक्रोश को केवल अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वे समस्या का समाधान नहीं, समस्या का राजनीतिक दोहन करेंगे। यहां बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वे केवल तालियां बजाये या निंद करने तक सीमित हो गए तो लोकतंत्र कमजोर होगा। बुद्धिजीवी को सत्ता से भी प्रश्न पूछना चाहिए और विपक्ष से भी। उसे राष्ट्रवाद के नाम पर हो रहे राजनीतिक ध्रुवीकरण पर भी बोलना चाहिए और विपक्ष की उग्र राजनीति पर भी। लोकतंत्र में तटस्थता का अर्थ चुप्पी नहीं, बल्कि समान कसौटी है। नेताओं को भी चेतावनी समझनी होगी,देश चुनावों से चलता है, लेकिन केवल चुनावों के लिए नहीं चलता। आज यदि हर मुद्दे को चुनावी चरम से देखा जाएगा तो शिक्षा रोजगार से पीछे चली जाएगी, विकास आरोप-प्रत्यारोप में दब जाएगा और राष्ट्रहित दलगत हितों में उलझ जाएगा।

राजनीतिज्ञों को यह याद रखना होगा कि चुनाव पांच साल के होते हैं, लेकिन समाज पीढ़ियों तक रहता है। इसलिए राहुल गांधी की आक्रामकता हो या मोदी-शाह का पलटवार, योगी-अखिलेश का संघर्ष हो या अन्य नेताओं की बयानबाजी-हर किसी को अपनी राजनीतिक सीमा पहचाननी होगी। सत्ता को अहंकार से और विपक्ष को अति-आक्रामकता से बचना होगा। जनता को भी अब केवल नारा पढ़ने नहीं, काम पर वोट करना सीखना होगा। उसे पूछना होगा-राष्ट्रवाद की बात करने वालों ने राष्ट्र के लिए क्या किया? सरकार से सवाल करने वालों के पास समाधान क्या है?

युवाओं के भविष्य की चिंता करने वाले उनके लिए कौन-सी ठोस नीति लेकर आए हैं? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार नारा नहीं, जागरूक मतदाता है। देश को वंदे मातरम् पर लड़ने वाले नेता नहीं, व्यवहार में उतारने वाले नेता चाहिए। राष्ट्रवाद की आग इतनी न भड़काए कि उसमें लोकतंत्र ही जल जाए। याद रखिए कि देश बड़ा है, दल छोटे हैं। संविधान बड़ा है, सत्ता छोटी है। जनता बड़ा है, नेता उसके प्रतिनिधि हैं। राजनीति यदि यह भूल गई तो जनता के उसे याद दिलाना होगा और यह काम केवल मतपेटी के दिन नहीं, हर दिन जागरूक नागरिक बनकर करना होगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, वे उनके अपने विचार हैं।)

पैसा और शोहरत से बड़ी है ये ताकत!



स्वामी विवेकानंद की सीख जीवन का नजरिया बदल देती है। पैसा और शोहरत से बड़ी ताकत आंतरिक मजबूती है। इसे अपनाकर जीवन वास्तव में सफल और सार्थक बनाया जा सकता है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती हैं। कभी साधन कम होते हैं, तो कभी मेहनत के बावजूद नतीजा नहीं

संसार में दो ही हठी और दो ही मेहमान



माता सरस्वती और महाकवि कालिदास से जुड़ा ये दिलचस्प प्रसंग। एक बार कालिदास पड़ोसी राज्य में शाश्वत् कर देने जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में प्यास लगी। सामने उन्हें एक था और उसके पास एक झोपड़ी। जब वो झोपड़ी के सामने पहुंचे, तो झोपड़ी से एक बच्ची बाहर निकली। उसने कूर्प से पानी परा



संकलित

दर्शन

मिलता है। हर बार पारोस्थांतया को दाष दत रहन स व्याक्त कमजार हाता जाता है। विवेकानंद की सीख है कि सही समय का इंतजार करने के बजाय जो साधन उपलब्ध हैं उन्हीं से शुरुआत करें। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेने वाला व्यक्ति धीरे-धीरे अपनी राह खुद बना लेता है। शिकायत की बजाय प्रयास ज्यादा काम आता है। आजकल दूसरों से तुलना करना बहुत आसान हो गया है। किसी की सफलता देखकर लगता है कि हम पीछे रह गए। लेकिन हर किसी की यात्रा अलग होती है। दूसरों से तुलना करने की बजाय अपनी क्षमता को पहचानना ज्यादा जरूरी है। स्वामी विवेकानंद याद दिलाते हैं कि आपके अंदर आगे बढ़ने की शक्ति पहले से मौजूद है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और सही दिशा देने की है। खुद पर भरोसा, जिम्मेदारी और मुश्किल में डटे रहने की आदत जब बन जाती है तो सफलता व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यही भीतर की ताकत जिंदगी को सच में सफल बनाती है।



संकलित

प्रेरणा

अंतर्मन



करंट अफेयर

चार दशक की युद्ध तैयारी से ईरान को मिली राहत

भारतीय सैन्य विशेषज्ञ ने कहा कि ईरान ने अमेरिका के साथ संभावित युद्ध के लिए चार दशक तक तैयारी की थी, जिसमें उसके शीर्ष नेतृत्व के खत्म होने जैसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारी भी शामिल थी, यही वजह है कि उसके विरोधियों के लिए ईरान को पूरी तरह तबाह करना मुश्किल हो रहा है। 'ऑर्गनॉल रिसर्च फाउंडेशन (ओआरएफ) अमेरिका' की ओर से शुक्रवार को वाशिंगटन में आयोजित एक परिचर्चा में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस दिल्ली ने कहा कि अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष में भारी नुकसान उठाने के बावजूद ईरान में लंबा खींचने वाला युद्ध लड़ने की क्षमता है। भारत की रक्षा खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख दिल्ली ने कहा कि इस युद्ध से सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी भी सैन्य अभियान का राष्ट्रीय लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उससे बाहर निकलने की रणनीति पहले से तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा, युद्ध शुरू करने से पहले कुछ बातें जानना जरूरी है। आपका घोषित राष्ट्रीय लक्ष्य आपके लिए, आपके सेना और सरकार में मौजूद लोगों के लिए स्पष्ट होना चाहिए। यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि युद्ध के किस चरण में आप जीत की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इसके बाद निकास रणनीति आती है, खासकर तब जब युद्ध किसी दूसरे देश में लड़ा जा रहा हो।



2.07 करोड़ रुपये में बिकी – यानी अपने अनुमान से 25 गुना ज्यादा। इसी तरह शांति देे की बिना शीर्षक वाली पेंटिंग (1971) को लेे तो वह लगभग 32–45 लाख रुपये के अनुमान के मुकाबले 3.25 करोड़ रुपये में बिकी। ऐसी बिक्री ने भारतीय कलाकारों के लिए एक चलन बना दिया है। पत्रिका 'लवस्टोप' के अनुसार, यह बाजार लगभग 3,000 करोड़ रुपये का है, जो सदी की शुरुआत में कुछ करोड़ रुपये ही था। यह सब दिखाता है कि भारतीय कला का दायरा सिर्फ कुछ महंगे सौंदर्य से कहीं आगे बढ़ रहा है।



प्रोडक्शन लिंक इसेटिव

मोर्ट प्रोडक्शन लिंक पब्लिशिंग (उत्पादन से जुड़ी सजा) से 'प्रोडक्शन लिंक इसेटिव' (उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन) की ओर बढ़ गया है। एक समय था जब तय सीमा से ज्यादा उत्पादन कराने पर कंपनी को सजा दी जाती थी! - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आत्मनिर्भर भारत

राष्ट्रीय आंतरिक्ष दिवस पर, हम अपने युवा वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और उद्यमियों को ललाना करते हैं, जिसकी सेवा, इन्फोहेलन और लगन हमारी क्षमताओं का दायरा लगातार बढ़ा रही है। उनकी उत्साहियता एक आत्मनिश्वास से भरे और आत्मनिर्भर भारत की भावना को द्वाती है। - डॉ. एस. जयशंकर, विदेश मंत्री

महिला सशक्तिकरण

राहुल गांधी नव से महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं को अधिकार दिलाने की दिशा में सबसे दृष्टिकारी अंग्रेज, यानी महिला आंदेशन विरोधक का विरोध करते हैं और उसके खिलाफ वोट देते हैं। - अखिलेश यादव, सांसद, सपा

मातृभाषा का सम्मान

हर राज्य की मातृभाषा का सम्मान और उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी भाषा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इससे देश की भाषाई और भावनात्मक एकता में दूरियां और मतभेद पैदा होते हैं।



पूर्व केन्द्रीय मंत्री गुरुदास कामत की 8वी पुण्यतिथि मनाई गई

मुंबई: पूर्व केन्द्रीय मंत्री और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय गुरुदास कामत की 8 वी पुण्यतिथि अंधेरी पश्चिम के डी. एन. नगर कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को सुबह मनाई गई।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छगग)
रा०प्र०क्र०- /3-6/2025-26
ईशतहार
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सुमित सोनी आ० अशोक प्रसाद व अन्य निवासी पूर्वी परासी थाना अपनरा पोस्ट रेनुसगण जिला सोनभद्र उ०ग० के द्वारा के द्वारा ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 400 रकबा 0.781 हे० भूमि के राजस्व अभिलेखों में वसीयतनामा दिनांक 18.02.2020 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 16.09.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक:- 24/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर। अक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी
तहसीलदार अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छगग)
रा०प्र०क्र०- /ब- 121/2025-26
ईशतहार
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक दीपिका अग्रवाल पति राजेश अग्रवाल निवासी 52/2 वार्ड नंबर 1 एमजी रोड अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छगग के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 157/575 रकबा 0.015 हे० भूमि को अनावेदक फुकेरा अग्रवाल पिता सत्यनारायण अवाल एमजी रोड पंजाब गार्डन के सामने अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छगग के पास अंकन राशि रुपए 5,40,000/- में बिक्री करने का सोदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 21.09.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक:- 21/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
तहसीलदार अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छगग)
रा०प्र०क्र०- /ब- 121/2025-26
ईशतहार
एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक नेपाल आ०कालिलाल निवासी ग्राम सुभाषनगर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छगग के द्वारा अपने स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि ग्राम सुभाषनगर स्थित भूमि खसरा नंबर 126/110 रकबा 0.288 हे० भूमि को अनावेदक बबिता जायसवाल पति संजय कुमार जायसवाल निवासी अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छगग के पास अंकन राशि रुपए 40,00,000/- में बिक्री करने का सोदा तय कर बिक्री अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच एवं प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 07.09.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक:- 11/08/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।
तहसीलदार अम्बिकापुर

महिला प्रदर्शनकारियों की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट गंभीर जंतर-मंतर पर यौन उत्पीड़न की जांच पहले होगी, कमेटी जल्द अंतरिम रिपोर्ट करे दाखिल

एजेसी नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सोमवार को स्पष्ट किया कि जंतर-मंतर पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस हिंसा के आरोपों की जांच के लिए गठित हाई-पावर्ड एन्क्वायरी कमेटी महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोपों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करेगी।

सीजेआई ने कहा कि 18 अगस्त के आदेश के अनुसार, कमेटी को महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित यौन हिंसा, उत्पीड़न, छेड़छाड़ और अन्य प्रकार की हिंसा से जुड़ी शिकायतों पर प्राथमिकता से विचार करते हुए जल्द से जल्द अंतरिम रिपोर्ट दाखिल करनी है। यह मामला तब सामने आया, जब सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों द्वारा कथित छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की शिकायतें की हैं।



20 जुलाई के प्रदर्शन से उठा यह मामला कमेटी प्राथमिकता से विचार करे

महिलाओं की शिकायतों को मिलेगी प्राथमिकता

शीर्ष अदालत ने राज्यों से मांगा जवाब फुटपाथ पर कब होगी लोगों के चलने की व्यवस्था? यह जितंगी का अहम हिस्सा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुटपाथ लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे पैदल चलने वालों के निर्देशों के पालन पर जवाब दें। बेंच ने सड़क वाली जगहों पर सही ढंग से फुटपाथ बनाने के मामले में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। बेंच ने कहा कि पहला कदम पैदल चलने वालों के लिए जगह को सही ढंग से चिह्नित करना है।

इसी मुद्दे पर अलग हिट याचिका भी दायर

इस पर जस्टिस जॉयमल्य बागची ने बताया कि इसी मुद्दे को लेकर एक अलग रिट याचिका भी दायर की गई है और हाई-पावर्ड कमेटी को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है। सीजेआई ने कहा कि कमेटी के अध्यक्ष को शिकायतें प्राप्त करने के लिए नोटल अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। नोटल अधिकारियों की नियुक्ति के बाद शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया सार्वजनिक की जाएगी।

कमेटी को विशेष रूप से महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित लक्षित हिंसा, उत्पीड़न, छेड़छाड़ और किसी भी प्रकार के द्वितीयक उत्पीड़न की शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने को कहा गया है। इसके साथ ही पुलिस बल के कथित अत्यधिक इस्तेमाल और छेड़छाड़ के आरोपों पर जल्द से जल्द अंतरिम रिपोर्ट दाखिल कराने का निर्देश दिया गया है।

जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर सुको मे सुनवाई झारखंड सरकार और केंद्र को दिया नोटिस

14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने मामले में जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह जनहित याचिका प्रार्थी हरिशरण देवान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की गई है।

आरक्षण पर चिराग पासवान की दो टूक ये खैरात नहीं, सांविधानिक अधिकार, कोई समझौता नहीं

एजेसी पटना

स्थापित की गई थी और दुनिया की

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख और केन्द्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि जाति आधारित आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सांविधानिक अधिकार है। वहीं, विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल किसी के कह देने भर से आरक्षण खत्म करने के लिए किसी के कह देने भर से आरक्षण खत्म किया जा सकता है? यह सांविधानिक अधिकार है।

कोई ताकत इसे कमजोर नहीं कर पाएगी। जब तक मैं, रामविलास पासवान का बेदा, इस सरकार का हिस्सा हूँ, मैं इस व्यवस्था से समझौता नहीं होने दूंगा। पासवान ने कहा कि विपक्षी दल हर चीज में राजनीति देखते हैं। आखिर संघ, भाजपा और हमारी पार्टी सभी एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं? क्या किसी के कह देने भर से आरक्षण खत्म किया जा सकता है? यह सांविधानिक अधिकार है।

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री को राज्य में हाल ही में आई विनाशकारी बाढ़ से हुए नुकसान, राहत कार्यों और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में असम से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। सीएम ने गृह मंत्री को बाढ़ से हुई तबाही के पैमाने और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत, पुनर्वास व पुनर्निर्माण कार्यों



गृह मंत्री शाह से मिलते सीएम हिमंता

के बारे में अवगत कराया। गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ से हुए नुकसान की गंभीरता को स्वीकार करते हुए असम सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

स्कूली रसोइया के वेतन डबल होने व उपहार से खिले चेहरे

संवाददाता

चित्रकूट। म्पाननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा रसोइया सम्मान समारोह एवं कैशलेश चिकित्सा कार्ड वितरण के

सजीव प्रसारण दिखाए जाने संबंधी कार्यक्रम ब्लॉक मऊ सभागार में आयोजित किया गया। तहसील स्तरीय उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी ने रसोइया

को बड़े हुए मानदेय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हुए एम ओ यू के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा हेतु दो लाख रुपए, प्रतिवर्ष रसोइयों के समस्त परिवार को पांच लाख रुपए तक का निःशुल्क

चिकित्सा सुविधा, रसोइयों को प्रतिवर्ष यूनियन में हेतु मिलने वाले पांच सौ रुपए से एक हजार रुपए करने की जानकारी दी और समस्त रसोइया को अपनी ओर से उपहार स्वरूप साड़ी वितरण कर

सम्मानित किया। खंड शिक्षा अधिकारी कृष्ण दत्त पाण्डेय द्वारा समस्त अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन करने के साथ ही तहसील मऊ के दोनों ब्लॉक रामनगर एवं मऊ से उपस्थिति सभी

शिक्षकों, रसोइयों मीडिया से उपस्थित समस्त बंधुओं का स्वागत सम्मान करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग में रसोइयों का महत्व बताते हुए विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी।

‘एक देश, एक चुनाव’ का विरोध कांग्रेस और टीएमसी ने संसदीय समिति की बैठक में किया विरोध



एजेसी नई दिल्ली

पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का संसद की संयुक्त समिति के समक्ष जोरदार विरोध किया। उन्होंने इस पहल को भयानक और असंवैधानिक बताया। पूर्व गृह और वित्त मंत्री ने कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' के तहत पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव बिना सोचे-समझे किया गया प्रयास है। चिदंबरम ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पेश होकर अपनी राय रखी।

निर्वाचन आयोग को मिल जाएंगे बेलगाम अधिकार: टीएमसी

समिति की सदस्य और तृणमूल कांग्रेस की नेता सागरिका घोष ने विधेयक का विरोध करते कहा कि इससे निर्वाचन आयोग को बेलगाम अधिकार मिल जाएगा। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता



वाली समिति के समक्ष पद्य पुरस्कार से सम्मानित करीब 10 लोगों के एक समूह ने भी अलग से अपनी राय रखी। इनमें तरलोचन सिंह, नवीन खन्ना, मीनाक्षी जैन और नीरू कुमार शामिल थे। पद्य पुरस्कार विजेताओं में से कुछ ने एक साथ चुनाव कराने की पहल का समर्थन किया, जबकि अन्य ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों ने कहा कि इससे देश में अराजकता पैदा हो सकती है। ये दोनों विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में पेश किए गए थे।

उच्च स्तरीय समिति ने की थी सिफारिश

इन विधेयकों को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद तैयार किया गया था। समिति ने चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोविंद की अध्यक्षता वाली इस उच्चस्तरीय समिति के सदस्य थे। संविधान लागू होने के बाद 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी यह व्यवस्था जारी रही। हालांकि, कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 में एक साथ चुनाव कराने का यह चक्र टूट गया।

दिल्ली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त



इलाके और सड़कें झील में तब्दील

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में सावन के आखिरी सोमवार को सुबह से ही बारिश की झड़ी लग गई। जिससे



दिल्ली के संगम विहार इलाके में जलभराव में फंसी स्कूली छात्राएं

जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कई जगह जलभराव और पेड़ गिरने से आवागमन ठप हो गया। इसके कारण विभिन्न स्थानों पर यातायात जाम की स्थिति बन गई। कई इलाकों में सड़कें झील में तब्दील हो गई। करीब दो से तीन फीट तक पानी भर जाने से हालात बदतर हो गए। कई इलाकों में दो से तीन फीट तक पानी जमा हो गया। इससे पैदल यात्रियों के साथ वाहन चालकों को भी परेशानी हुई। सुबह करीब 10 बजे बारिश शुरू हुई और दोपहर 12 से एक बजे के बीच तेज बारिश के काहण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति गंभीर हो गई।

बहनों ने बांधी स्नेह की डोर, विष्णु भैया ने दिया सुरक्षा और सम्मान का भरोसा

बहनों के स्नेह से सजी ह्यविष्णु भैयाह की कलाई, सुरक्षा-सम्मान का लिया संकल्प

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। रक्षाबंधन के पावन पर्व से पहले राजधानी रायपुर में आज भाई-बहन के स्नेह और राष्ट्ररक्षा के संकल्प का भावपूर्ण संगम देखने को मिला। बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित हस्नेह की डोरह् कार्यक्रम में केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस के जवानों की कलाईयों पर जब स्कूली बेटियों, दिव्यांग बेटियों और महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों ने रक्षा सूत्र बांधे तो पूरा वातावरण आत्मीयता, सम्मान और कृतज्ञता के भाव से भर उठा। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब

वर्ष 2017 में रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पूर्व नक्सली मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए शहीद उपनिरीक्षक श्री युगल किशोर वर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री इस अवसर पर भावुक हो उठे। उन्होंने शहीद वर्मा के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए शहीद जवानों के परिवारों के साथ सदैव खड़े रहने का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राखी का यह धागा केवल भाई-बहन के स्नेह का बंधन नहीं, बल्कि एक शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। हमारे वीर जवानों का बलिदान

और उनके परिवारों का त्याग छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूल सकता। शहीदों के परिवार हमारे अपने परिवार हैं और उनके सम्मान, स्वाभिमान तथा हर सुख-दुःख में उनके साथ खड़े रहने का यह रिश्ता सदैव अटूट रहेगा।

नक्सलवाद के अंत से बहनों को मिला सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि देश और छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कराने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने



अदम्य साहस का परिचय दिया है और अनेक जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। नक्सलवाद के अंत की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ हमारी बहनों के लिए सुरक्षा और विश्वास का सबसे बड़ा उपहार है। अब वह समय आ रहा है जब नक्सल हिंसा के कारण किसी

बहन का सुहाग नहीं उड़जेगा, किसी मां को अपना बेटा नहीं खोना पड़ेगा और किसी बहन को अपने भाई के सकुशल घर लौटने की चिंता नहीं सताएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा सुरक्षा बलों के साहस

और पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक सफलता ने बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में शांति और विकास के नए युग का मार्ग प्रशस्त किया है। इस परिवर्तन में बस्तर की जनता का विश्वास और सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बस्तर की पहचान हिंसा से नहीं, बल्कि शांति, विकास, समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पर्यटन और नई संभावनाओं से होगी। लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण विकास से वंचित रहे क्षेत्रों तक सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और रोजगार के अवसर तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। सरकार का

संकल्प बस्तर को देश के श्रेष्ठ और विकसित आदिवासी अंचलों में शामिल करना है।

जवानों की कलाईयों पर सजी बहनों की राखी

स्नेह की डोर कार्यक्रम में सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सेना और पुलिस के लगभग 800 जवान शामिल हुए। स्कूली छात्राओं, दिव्यांग बेटियों, स्वच्छता दीदियों, ड्रोन दीदियों, लखपति दीदियों और महिला स्व-सहायता समूहों की बहनों ने जवानों की कलाईयों पर राखी बांधी और राष्ट्र तथा समाज की सुरक्षा में उनके योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा आत्मीय और

अद्भुत दृश्य पहली बार देखा है। देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए घर-परिवार से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले जवानों को जब इतनी बड़ी संख्या में बहनों ने राखी बांधी तो रक्षाबंधन का पर्व अपने व्यापक अर्थ में साकार होता दिखाई दिया। हमारे जवान केवल सीमाओं और समाज के सुरक्षा प्रहरी नहीं, बल्कि प्रदेश की बहनों के भाई भी हैं। इस अवसर पर सुरक्षा बलों के जवानों ने भी बहनों की रक्षा, सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के जवानों के शौर्य और समर्पण को नमन करते हुए नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जवानों का सम्मान किया।

उद्योग मंत्री की पहल से कोरबा शहर के मुख्य मार्गों के डामरीकरण के लिए 17.50 करोड़ स्वीकृत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

कोरबा। कैबिनेट मंत्री एवं नगर विधायक लखन लाल देवांगन के प्रयासों से कोरबा शहर के मुख्य मार्गों के नए सिरे से डामरीकरण के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से 17.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। मंत्री देवांगन के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन ने 13 सड़कों के डामरीकरण के लिए स्वीकृति आदेश जारी किया है। मानसून खत्म होते ही कार्य शुरू कराया जाएगा।

इन सड़कों के लिए राशि जारी – सोनालिया ब्रिज स्टेशन रोड से सीतामढ़ी मुख्य मार्ग तक – 87.75



लाख, शारदा विहार फाटक से टीपी नगर फाटक तक – 40 लाख, डीडीएम रोड से बस स्टैंड तक – 1.64 करोड़, सोनालिया ब्रिज से तुलसी नगर बायपास तक – 1.99 करोड़, सुभाष चौक से सब स्टेशन तक – 97.80 लाख, नेहरू नगर में डामरीकरण – 55 लाख, पोड़ीबहार चर्च से लकी बिग बॉस्केट मोड़ तक – 1.65 करोड़, कलेक्ट्रेट एटीएम से

बैगिनडभार आंगनबाड़ी तक – 66.18 लाख, लालघाट बालको चेक पोस्ट से रिश्दा चौक तक – 1.20 करोड़, रिश्दा चौक से गायत्री मंदिर मुख्य मार्ग तक – 1.80 करोड़, सरदार पटेल नगर आवासीय क्षेत्र – 1.50 करोड़, सरदार पटेल नगर व्यावसायिक क्षेत्र – 1.45 करोड़, प्रेम नगर मुख्य मार्ग से कपलमुड़ा डीपरा बस्ती तक मरम्मत – 1.38 करोड़ इसके अलावा 6 प्रमुख मार्गों के लिए पहले स्वीकृत 7.12 करोड़ रुपये के टेंडर पूरे हो चुके हैं।

इनमें सुनालिया ब्रिज से पावर हाउस रोड, पावर हाउस से पुराना बस स्टैंड, जैन चौक से घंटाघर चौक, घंटाघर से कोसाबाड़ी चौक सहित अन्य मार्ग शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। आईसीएआर-राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएसएम), रायपुर द्वारा किसानों के बीच घरेलू पोषण सुरक्षा, आहार विविधता और सुरक्षित खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रपोषण वाटिका पर एक दिवसीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बरोदा, मुरा, बेलदुकरी, देवगांव, कुरा और कथुरा गांवों के 62 किसानों ने हिस्सा लिया, जिनमें 10 महिला किसान भी शामिल थीं।

कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉ. पी. के. राय ने किया। उन्होंने पोषण वाटिका के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा



कि घर पर ताजी, पौष्टिक और रसायन मुक्त सब्जियों व फलों की उपलब्धता परिवार की सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने

बताया कि जिन परिवारों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है, वे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण वाटिका विकसित कर सकते हैं, जिससे

समुदाय स्तर पर कुपोषण दूर करने में मदद मिलेगी।

उज्जत तकनीकों और जैविक खेती पर जोर

संयुक्त निदेशक एवं कार्यक्रम समन्वयक डॉ. पंकज शर्मा ने किसानों को स्थानीय जलवायु के अनुसार पोषण वाटिका प्रबंधन के व्यावहारिक सुझाव दिए। बारिश कम होने पर सही आकार के गड्ढे बनाकर, उनमें गोबर की सड़ी खाद मिलाकर फलदार पौधे लगाए। जलभराव से बचाव के लिए उचित जल निकासी का प्रबंध करें और अधिक नमी वाले क्षेत्रों में सब्जियों के लिए ढ़ंची उठी हुई (रेज्ड) क्यारियां तैयार करें। अनावश्यक रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से बचकर

पारंपरिक और पर्यावरण-अनुकूल जैविक उपायों को अपनाएं।

सब्जियों के बीज और पौधों का वितरण

कार्यक्रम के अंत में किसानों को पोषण वाटिका स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्नत किस्म के अमरूद और नींबू के पौधों के साथ-साथ 18 प्रकार की सब्जियों (पालक, धनिया, मेथी, भिंडी, लौकी, तोरी, मूली आदि) के बीज निशुल्क वितरित किए गए। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच श्रीमती कंचन गायकवाड़ एवं संतोष कुंरे विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल समन्वय प्रधान वैज्ञानिक डॉ. के. सी. शर्मा द्वारा किया गया।

छत्तीसगढ़ पर्यटन को मिलेगी वैश्विक उड़ान, 2028 तक नई पहचान बनाने का लक्ष्य : मंत्री राजेश अग्रवाल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यटन को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सरकार दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है। वे आज नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस वार्ता में विभागीय उपलब्धियां गिना रहे थे।

मुख्य बातें – पर्यटन में निवेश : फिल्म सिटी

के लिए 203.53 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। फिल्म सिटी व कन्वेंशन सेंटर पर 350 करोड़ की लागत से कार्य प्रस्तावित है। 18 पर्यटन संपत्तियों को लीज-सह-विकास मॉडल से विकसित किया जाएगा, जिससे 500 करोड़ निवेश और 1000 रोजगार की संभावना है। धार्मिक पर्यटन : श्री रामलला दर्शन योजना के तहत 61 ट्रेनों से 50 हजार से अधिक श्रद्धालु अयोध्या-काशी के दर्शन कर चुके हैं। भोरमदेव कोरिडोर के लिए भारत सरकार ने 145.99 करोड़ स्वीकृत किए हैं।



स्थानीय रोजगार : होमस्टे को बढ़ावा, 390 दूर ऑपरेंटर और 26 होटल पंजीकृत। 1500 युवाओं को गाइड, हॉस्पिटैलिटी व डिजिटल कंटेंट में प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य। ऑनलाइन बुकिंग से 6.48 करोड़

और पर्यटन इकाइयों से 31.75 करोड़ का राजस्व मिला।

विश्वस्तरीय गंतव्य : चित्रकोट को विश्वस्तरीय पर्यटन गंतव्य, सिरपुर का एकीकृत मास्टर प्लान और मैनपाट-जशपुर में सुविधाओं का विस्तार। सिरपुर को यूनेस्को

विश्व धरोहर के लिए नॉमिनेशन डोजियर भेजा गया है।

संस्कृति संरक्षण : कलाकार कल्याण कोष से 70 कलाकारों को 30.03 लाख, लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना से 87 कलाकारों को 19.08 लाख और 407 वरिष्ठ कलाकारों को 82.12 लाख पेंशन के रूप में दिए गए। 363 संस्थाओं को 854 आयोजनों के लिए 7.85 करोड़ का अनुदान। बस्तर पंडुम, पावस प्रसंग, रंगतरंग जैसे आयोजन और संस्कृति का डिजिटल आर्काइव तैयार हो रहा है।

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में संसदीय संकुल विकास परियोजना मिनवाखाड़ पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में जशपुर जिले के मिनवाखाड़ क्षेत्र में संचालित संसदीय संकुल विकास परियोजना के तहत हुए विकास कार्यों, नवाचारों और ग्रामीण सशक्तिकरण की पहल को विस्तार से दर्शाया गया है। इस अवसर पर कृषि एवं आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार



नेताम, विधायक प्रबोध मिंज सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने पुस्तक की सराहना

करते हुए कहा कि इस तरह के दस्तावेजीकरण से विकास मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी अपनाने की प्रेरणा मिलेगी।

वन विभाग और ग्रामीणों की सजगता से दो तेंदुआ शावकों को मिला मां का साथ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। बस्तर के घने जंगलों में वन विभाग और ग्रामीणों की संवेदनशीलता से तेंदुए के दो बिछड़े शावकों को सुरक्षित उनकी मां से मिलाने का सफल अभियान पूरा हुआ। करीब 48 घंटे तक चले इस अभियान में वन अमले ने लगातार निगरानी रखी और शावकों को उनकी मां तक पहुंचाने के लिए पूरी सावधानी बरती।

यह अभियान वन मंत्री केदार कश्यप के वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के संकल्प को धरातल पर साकार करने का उदाहरण है। अभियान में वन विभाग की तत्परता के साथ ग्रामीणों का सहयोग भी महत्वपूर्ण रहा। 122 अगस्त को चित्रकोट रेंज के पहाड़ी वन क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों द्वारा तेंदुए का एक छोटा शावक



उठाए जाने की सूचना वन विभाग को मिली। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हुई। वन मंडलाधिकारी दीपेश कपिल के मार्गदर्शन में वन अमले ने रात करीब 11.20 बजे शावक को सुरक्षित अपने संरक्षण में लिया। वन विभाग ने शावक को उसकी मां से मिलाने के लिए उसे तड़के करीब 4 बजे घने जंगल में बिस्मि के पहाड़ी वन क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों द्वारा तेंदुए का एक छोटा शावक

शावक को वहां से ले जाया। हालांकि, अगले दिन निगरानी के दौरान मां के शावक तक नहीं पहुंचने की जानकारी मिली।

दूसरे शावक की भी हुई तलाश पहले प्रयास के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों के सहयोग से आसपास के क्षेत्र में दूसरे शावक की तलाश शुरू की। जल्द ही दूसरा शावक भी मिल गया। दोनों शावकों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया और उनकी गतिविधियों पर

नजर रखने के लिए आसपास हाई-रिजोल्यूशन ट्रैप कैमरे लगाए गए। वन अमले ने करीब 48 घंटे तक लगातार निगरानी की। इस दौरान शावकों की सुरक्षा और उनकी मां तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हर गतिविधि पर नजर रखी गई।

कैमरे में कैद हुआ मां का ममता भरा दृश्य

लगातार निगरानी के बाद सोमवार रात ट्रैप कैमरे में वह दृश्य दिखाई दिया, जिसका वन विभाग और ग्रामीणों को इंतजार था। मादा तेंदुआ अपने दोनों शावकों के पास पहुंची और उन्हें सुरक्षित अपने साथ घने जंगल की ओर ले गई। शावकों के अपनी मां से मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने राहत की सांस ली। इस तरह 48 घंटे का मिशन रीयूनइट सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

वन्यजीव संरक्षण में संवेदनशीलता की मिसाल

यह अभियान केवल एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, बल्कि वन्यजीवों के प्रति संवेदनशीलता और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व की मिसाल है। वन विभाग ने शावकों को अनावश्यक रूप से अपने पास रखने के बजाय उनकी मां से मिलाने को प्राथमिकता दी। ग्रामीणों की सजगता, वन अमले की तत्परता और आधुनिक निगरानी तकनीक के समन्वय से दो नए शावकों को उनका प्राकृतिक परिवार वापस मिल सका। यह सफलता बताती है कि वन्यजीव संरक्षण केवल विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वन विभाग और स्थानीय समुदाय के साझा प्रयासों से ही अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने की सौजन्य भेंट

महिला अधिकार, जागरूकता और सशक्तिकरण को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन पर हुई चर्चा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। महिला अधिकारों के संरक्षण, महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर विस्तार से महत्वपूर्ण चर्चा हुई। डॉ. ममता साहू ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल एवं प्रभावी आयोजन के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया। कार्यक्रम के माध्यम



से महिलाओं के अधिकारों, उनके संरक्षण से जुड़े प्रावधानों तथा उपलब्ध सहायता तंत्र की जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रस्तावित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराने तथा जमीनी स्तर पर जागरूकता को और मजबूत करने

का प्रयास किया जाएगा। डॉ. ममता साहू ने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों की जानकारी देना सशक्तिकरण की पहली सीढ़ी है। राष्ट्रीय महिला आयोग के मार्गदर्शन से छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से आयोजित कर महिलाओं तक अधिकार एवं सुरक्षा संबंधी जानकारी पहुंचाने के प्रयासों को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा महिला अधिकारों, सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को केंद्र में रखते हुए जागरूकता एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को निरंतर बढ़ावा दिया जा रहा है।

महतारी वंदन की
किस्त से सजेगा
भाई का रक्षाबंधन



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह और आत्मीयता का प्रतीक है। ऐसे अवसर पर मिलने वाली छोटी-सी आर्थिक मदद भी त्योहार की खुशियों को और खस बना देती है। सूरजपुर जिले की निवासी श्रीमती कुंती साहू के लिए महतारी वंदन योजना की किस्त रक्षाबंधन से पहले ऐसी ही खुशियों की सौगात लेकर आई है।

श्रीमती कुंती साहू बताती हैं कि रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने के साथ मिठाई और उपहार देने की इच्छा हर बहन की होती है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती कीमतों के बीच इन छोटी-छोटी खुशियों के लिए भी सोच-समझकर खर्च करना पड़ता है। ऐसे में महतारी वंदन योजना से मिली राशि उनके लिए आर्थिक संबल बनी है। अब वे अपने भाई के लिए राखी, मिठाई और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार ले सकेंगी।

भावुक होते हुए श्रीमती कुंती साहू ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले यह राशि मिलने पर लिए बहुत खुशी की बात है। अब मैं अपने भाई के लिए राखी, मिठाई और उपहार ले पाऊंगी। इस सौगात के लिए विष्णु भैया, मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देती हूं। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली नियमित सहायता महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के साथ उनके जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों की खुशियों में भी सहभागी बन रही है। कुंती साहू के लिए इस बार का रक्षाबंधन इसी आत्मीय एहसास के साथ और भी यादगार होगा।

टेट के खिलाफ शिक्षकों का शक्ति प्रदर्शन, टेट मुक्ति नारो के साथ निकाली रैली

मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा, वेतन विसंगति, पुरानी सेवा गणना, बीएड ब्रिज कोर्स तथा भर्ती-पदोन्नति नियमों से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण की मांग को लेकर सोमवार को जिला मुख्यालय में

किया गया। यहां जिला मुख्यालय में भी शिक्षक हाथों में मांगों से संबंधित तस्खियां लेकर रैली में शामिल हुए और नारेबाजी के माध्यम से शासन का ध्यान शिक्षकों से जुड़े लंबित विषयों की ओर आकर्षित किया। रैली के दौरान

बनी हुई है। संगठन ने सरकार से मांग की कि सेवारत शिक्षकों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर स्पष्ट, व्यावहारिक और न्यायसंगत समाधान निकाला जाए। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से विद्यालयों में सेवाएं देते हुए

मामले में भी शीघ्र निर्णय लेने की मांग की। संगठन का कहना है कि बड़ी संख्या में शिक्षक लंबे समय से इस संबंध में शासन स्तर पर स्पष्ट निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिक्षकों ने सरकार से प्रक्रिया को शीघ्र आगे बढ़ाते हुए आवश्यक

दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की।

ज्ञापन में भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2026 में मौजूद असंतुलन एवं विसंगतियों को दूर करने की मांग भी प्रमुखता से शामिल रही। संगठन ने कहा कि शिक्षक संघों से जुड़े नियम स्पष्ट, व्यावहारिक और न्यायसंगत होने चाहिए, ताकि भर्ती एवं पदोन्नति की प्रक्रिया में अनावश्यक विवाद और असमंजस की स्थिति

उत्पन्न न हो। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने कहा कि यह टेट मुक्ति रैली केवल एक आंदोलनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश के शिक्षकों की लंबित समस्याओं को शासन के समक्ष मजबूती से रखने का सामूहिक प्रयास है। संगठन ने सरकार से अपेक्षा जताई कि शिक्षकों की पांच सूत्रीय मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए समयबद्ध एवं सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

रैली के माध्यम से शिक्षकों ने स्पष्ट संदेश दिया कि वे अपनी सेवा, सम्मान और भविष्य से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए लोकतांत्रिक एवं संगठित तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे।



शिक्षकों ने टेट मुक्ति रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित रैली में बड़ी संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भाग लिया और सरकार से लंबित मांगों पर ठोस एवं निर्णायक पहल की मांग की। रैली के पश्चात शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं संचालक के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पांच सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग की। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक केदार जैन, वीरेंद्र दुबे एवं संजय शर्मा के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों में एक साथ टेट मुक्ति रैली का आयोजन

जिला संचालक सचिन त्रिपाठी, यादवेंद्र दुबे एवं भूपेश सिंह ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से सेवा, सम्मान, वेतन एवं भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का विषय नहीं, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता और शिक्षकों के मनोबल से भी जुड़ा हुआ है। रैली का सबसे प्रमुख मुद्दा शिक्षक पात्रता परीक्षा की बाधिता रहा। शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे शिक्षकों के बीच टेट को लेकर नोकरी एवं सेवा सुरक्षा संबंधी चिंता

शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाले शिक्षकों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। रैली में शिक्षकों की पुरानी सेवा अर्थात् शिक्षकों की गणना का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय तक सेवा देने के बावजूद पुरानी सेवा अर्थात् अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाने से उनके आर्थिक एवं सेवा संबंधी हित प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षकों ने केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप वेतन व्यवस्था तथा विभिन्न शिक्षक संघों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग भी रखी। शिक्षकों ने बीएड ब्रिज कोर्स के

कांवरियों ने किया सिधेश्वर महादेव का जलाभिषेक

सावन के अंतिम सोमवार को पंचिरा में निकली भव्य कांवर यात्रा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। भगवान भोलेनाथ की आराधना के पवित्र सावन मास के अंतिम सोमवार को पंचिरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर में कांवरियों ने जलाभिषेक किया। कांवर यात्रा के लिए मंदिर समिति के द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी।

परंपरा के अनुसार सोमवार के प्रातः कांवर यात्रा के लिए पंचिरा समेत आसपास गांवों के बड़ी संख्या में श्रद्धालु रेणुका नदी के तट पर पहुंचे थे जहां धार्मिक मंत्रोच्चार के बीच कांवर में जल लेकर बाजे गाजे के साथ भोले

की भक्ति में झूमते हर हर महादेव व बोलबम के गगनभेदी जयघोष के साथ महिला, पुरुष व बाल कांवरिये प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे और सिधेश्वर



महादेव का जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर में भगवान सिधेश्वर महादेव की विशेष पूजा अर्चना कर क्षेत्र के सुख समृद्धि एवं खुशहाली हेतु कामना की

गई। शिवभक्तों के मंदिर पहुंचने और पूजा अर्चना का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा, जिससे गांव में मेले जैसा माहौल रहा।

आयोजन को सफल बनाने में संभागीय अध्यक्ष मनोज पांडे, मन्दिर समिति, कांवरिया समिति, रुद्र धर्म सेना, झांसी की रानी विश्रामपुर से आर्यन गुप्ता, ओकेश राजवाड़े, गौरी शंकर राजवाड़े, कुनाल गुप्ता, अमित भगत,

अशोक दुबे, अजय घोष, त्रिभुवन, करन रावत, स्नेहा मानिकपुरी, कोमल गुप्ता सहित अन्य धर्मप्रेमीयो का सराहनीय सहयोग रहा।

तरका आंबा केंद्र पहुंची कलेक्टर ने बच्चों से की आत्मीय संवाद, बांटी चाँकलेट

कलेक्टर की सहजता से प्रभावित बच्चों ने खुलकर की मन की बातें, बोले-फिर कब आईयेगा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। मंगलवार को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने भैयाथान विकासखंड के ग्राम पंचायत तरका में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र तरका-ब का निरीक्षण किया। जहां पद की औपचारिकता से

उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बच्चों से उनकी पढ़ाई, खेलकूद तथा केंद्र में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी चर्चा कर जानकारी ली और बड़े धैर्य से उनकी बातें सुनीं।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने एक बच्चे का वजन कराकर उसके पोषण स्तर की जानकारी ली तथा पोषण ट्रेकर एप का अवलोकन करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बच्चों को रोचक और सहज तरीके से सीखने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं तथा पोषण संबंधी गतिविधियों का संचालन



परे उन्होंने बच्चों के बीच दूरों पर बैठकर उनसे आत्मीय संवाद किया और उन्हें अपने हाथों से चाँकलेट वितरित की। कलेक्टर का यह सहज अंदाज नन्हे बच्चों को खूब भाया और बच्चों के साथ समूचा केंद्र उत्साहित हो उठा। कलेक्टर के आग्रह पर बच्चों ने हिंदी एवं अंग्रेजी वर्णमाला सुनाई। बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से भरी इस प्रस्तुति पर कलेक्टर सहित उपस्थित अधिकारियों ने तालियां बजाकर उनका

पूरी प्रभावशीलता के साथ किया जाए। कलेक्टर से हुए संवाद के बाद बच्चे बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने श्रीमती जमील से दोबारा आने का आग्रह भी किया। बच्चों की आत्मविश्वासपूर्ण प्रस्तुति से प्रसन्न होकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेन्द्र सिंह पाटले ने उन्हें सामूहिक रूप से पुरस्कृत किया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

तहसील कार्यालय के सामने स्थित विद्युत टावर पर चढ़ा युवक

पुलिस एवं 112 टीम की सूझबूझ से एक घण्टे की मसक़त के बाद ने नीचे उतरा युवक

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन चांदनी बिहारपुर। क्षेत्र में मंगलवार को उस समय हड़कप मच गया, जब नवगई चौक के समीप तहसील कार्यालय के सामने एक युवक विद्युत टावर पर चढ़ गया। युवक के विद्युत टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। ऊंचाई पर चढ़े युवक को देखकर लोगों में किसी बड़ी अनहोनी की आशंका बनी रही। मिली जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय शिवकुमार साकेत विद्युत टावर पर चढ़ गया था। बताया जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह विद्युत टावर के काफी ऊपर तक पहुंच गया था। मामले को गंभीरता को देखते हुए तत्काल सियाराम साहू ने 112 पुलिस सेवा को

सूचना दी। सूचना मिलते ही चांदनी बिहारपुर पुलिस एवं 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस जवानों ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए समझाइश शुरू की। युवक को विद्युत टावर से नीचे उतारना पुलिस के लिए आसान नहीं था। पुलिस एवं 112 की टीम ने काफी सावधानी के साथ युवक से बातचीत की और उसे नीचे आने के लिए समझाया। करीब एक घंटे की मशक़त और लगातार समझाइश के बाद युवक किसी तरह नीचे आने के लिए तैयार हुआ। इस दौरान चांदनी बिहारपुर पुलिस एवं 112 की टीम का युवक को सुरक्षित नीचे उतारने में अहम रोल रहा। टीम की सूझबूझ और तत्परता के चलते



नजर विद्युत टावर पर टिकी रही। पुलिस की तत्परता के कारण स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया। गौरतलब है कि चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में टावर पर चढ़ने की घटना पहले भी सामने आ चुकी है। पूर्व में चांदनी थाना परिसर में एक युवती मोबाइल

टावर पर चढ़ गई थी। उस समय भी पुलिस के सामने युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की चुनौती थी। पुलिस ने काफी देर तक समझाइश देकर किसी तरह युवती को सुरक्षित नीचे उतारा था। हालांकि मंगलवार की घटना उससे अलग थी, क्योंकि इस बार युवक मोबाइल टावर नहीं बल्कि विद्युत टावर पर चढ़ा था। विद्युत टावर पर चढ़ना बेहद जोखिम भरा माना जाता है और किसी भी प्रकार की चूक से गंभीर हादसा हो सकता था। ऐसे में पुलिस एवं 112 टीम की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई। युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आ रही है, हालांकि उसके टावर पर चढ़ने के वास्तविक कारणों की अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है।

कलेक्टर ने औद्योगिक इकाई से लेकर एकलव्य विद्यालय तक परखी जमीनी हकीकत

शासकीय कार्यालयों, योजनाओं एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की हकीकत जानने मौके पर पहुंची कलेक्टर



प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील सोमवार को जिले का सघन दौरा करते हुए शासकीय कार्यालयों, योजनाओं एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। दौरे की शुरुआत नयनपुर स्थित औद्योगिक परिक्षेत्र से हुई, जहां उन्होंने 10 मेगावाट के पावर प्लांट, सरिया निर्माण यूनिट तथा ब्रेड निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। पावर प्लांट की कार्यप्रणाली, रॉ मटेरियल एवं मशीनरी को बारीकी से समझते हुए उन्होंने संचालन में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। सरिया यूनिट में उत्पादन प्रक्रिया की पड़ताल कर उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों तथा संचालक को दिशा-निर्देशित किया, वहीं ब्रेड निर्माण इकाई में स्थापित मशीनों, उत्पादन लागत, आपूर्ति व्यवस्था तथा स्थानीय स्तर पर सृजित रोजगार के अवसरों पर चर्चा करते हुए स्वच्छता के कड़े मानकों के साथ उत्पादन करने पर बल दिया। इसके पश्चात कलेक्टर प्रशासनिक अमले के साथ भैयाथान पहुंचीं, जहां सबसे पहले तहसील एवं अनुविभागीय कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उन्होंने स्वयं कंप्यूटर सिस्टम पर

लंबित प्रकरणों की स्थिति खंगाली तथा फाइलों की पड़ताल की। निराकरण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने समय-सीमा के भीतर प्रकरण निपटाने की सख्त हिदायत दी। खाद्य एवं दाण्डिक शाखा तथा नकल शाखा में प्राप्त आवेदनों और पंजी का

प्रगति, राष्ट्रीय आजीविका मिशन बिहान की गतिविधियों तथा विकसित भारत जी रासीका योजना के कार्यों की समीक्षा की। लंबित आवास शीघ्र पूर्ण कराने और हितग्राहियों की समय पर किस्त जारी करने के साथ परिसर की स्वच्छता बनाए रखने पर उन्होंने विशेष जोर

सही तरीका अवश्य समझाया जाए। ग्राम पंचायत तरका में जल संचय से जुड़े कार्यों का अवलोकन कर कलेक्टर ने किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में ठोस कार्ययोजना बनाकर नवाचारों को अपनाया जाए।

दौरे के अंतिम चरण में उन्होंने एकलव्य मॉडल रेसीडेंसियल स्कूल ओडुंगी का निरीक्षण कर विद्यार्थियों की दर्ज संख्या की जानकारी ली और उनसे खेल गतिविधियों पर बातचीत की, जिस पर विद्यार्थियों ने बताया कि यहां खेलकूद के साथ



अवलोकन करने के साथ ही अभिलेखागार के अभिलेख भी देखे तथा कार्यालय पहुंचे आमजन से व्यवस्थाओं पर सीधी प्रतिक्रिया ली। तहसील न्यायालय में आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की समीक्षा कर उन्होंने शीघ्र निराकरण, पात्र हितग्राहियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने तथा आधार पंजीयन में निर्धारित शुल्क का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जनपद कार्यालय में उपस्थिति पंजी देखने के उपरान्त कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ स्वान कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास योजना की

दिया। शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान में उपलब्ध स्टॉक का मिलान करते हुए उन्होंने वितरण प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता बरतने की हिदायत दी। तत्पश्चात भैयाथान स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर उन्होंने मरीजों से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली तथा बच्चों के पोषण एवं उपचार की स्थिति परखी। शिशुवती माताओं से आत्मीय चर्चा करते हुए उन्होंने शिशु देखभाल संबंधी व्यावहारिक सुझाव साझा किए और चिकित्सा अमले को निर्देशित किया कि प्रत्येक माता को बच्चों की देखभाल का

योग जैसी गतिविधियां भी नियमित रूप से कराई जाती हैं। एकलव्य आवासीय बालिका छात्रावास एवं वहां संचालित रसोई का अवलोकन करते हुए उन्होंने साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेन्द्र सिंह पाटले, एसडीएम श्रीमती चांदनी कंवर, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी शुभम बंसल सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिप में हुआ पीएम राहत योजना पर एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण, गोल्डन आवर में त्वरित उपचार पर दिया गया जोर

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में जिला पंचायत सभाकक्ष में प्रधानमंत्री राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार उपलब्ध

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि दुर्घटना की स्थिति में वीडियो बनाने के बजाय घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करें, क्योंकि मानवीय संवेदनशीलता और त्वरित मदद से किसी की जान बचाई जा सकती है। गोल्डन

कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यशाला में एनआईसी के डीआईओ रोहन सिंह ने पीएम राहत योजना की रूपरेखा से अवगत कराया, वहीं डीआरएम जयप्रकाश मेथ्राम ने योजना के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ई-डार पोर्टल की क्रमवार प्रक्रिया समझाई ताकि प्रशिक्षणार्थी हैंड्स-ऑन अनुभव प्राप्त कर सकें। बताया गया कि पीएम राहत योजना एवं ई-डार का प्रमुख लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को समय

कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल की अध्यक्षता में आयोजित इस आयोजन में विभागीय



समन्वय को मजबूत बनाकर पीड़ितों का त्वरित उपचार सुनिश्चित कराने पर बल दिया गया। पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने कहा कि पीएम राहत योजना का मूल उद्देश्य किसी भी दुर्घटना पीड़ित को तत्काल उपचार एवं राहत सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय चिकित्सक और पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में होते हैं, इसलिए उनका दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

आवर के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री पटेल ने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद का समय उपचार की दृष्टि से सबसे निर्णायक होता है और इस अवधि में उचित इलाज मिल जाने पर घायल का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को गोल्डन आवर में बिना किसी विलंब के अस्पताल में भर्ती कर अधिकतम 7 दिनों तक प्रति व्यक्ति 1.50 लाख रुपये तक का

पर और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुलभ कराना है। इस अवसर पर पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक दुर्घटना पीड़ित तक समय पर इलाज पहुंचाने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में एसडीओपी अभिषेक पैकरा, समस्त थाना प्रभारी एवं विवेचक, सीसीटीएनएस ऑपरेटर सहित परिवहन, हाईवे तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

C
M
Y
K